



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 285]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 23, 2001/कार्तिक 1, 1923

No. 285]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 23, 2001/KARTIKA 1, 1923

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क मानविदेशालय)

अन्तिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2001

विषय :- चीन जनवादी गणराज्य से हाई फेराइट रिंग मैग्नेटस (एचएफआरएम) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा—अंतिम जांच निष्कर्ष

सं. 65/1/2000-डीजीएडी.—1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए;

क. प्रक्रिया

1. निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है :-

- (i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके पश्चात प्राधिकारी भी कहा गया है) को उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत मै0 डीजीपी हिनोडे इंडस्ट्रीज लि0, पुणे तथा मै0 जीपी इलैक्ट्रानिक्स लि0, नासिक (जिन्हें इस अधिसूचना में याचिकाकर्ता भी कहा गया है) की ओर से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है जिसमें चीन जनराज्य (जिसे एतद्पश्चात सम्बद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित हाई फेराइट रिंग मैग्नेटस (एचएफआरएम) (जिसे एतद्पश्चात सम्बद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा का अनुरोध किया गया है।
- (ii) याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्याप्त साक्ष्य के आधारपर प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य से एच एफ आर एम के आयातों की समीक्षा जांच आरम्भ करने का निर्णय लिया। प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित एच

एफ आर एम के आयातों के संबंध में समीक्षा जांच आरम्भ करते हुए दिनांक 23.12.2000 को भारत के राजपत्र, असाधारण में एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की ।

(iii) प्राधिकारी द्वारा दिनांक 12.7.1999 की अधिसूचना द्वारा सम्पन्न हुई जांच को इस अधिसूचना में "पूर्वतीं जांच" कहा गया है ।

(iv) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) से अनुरोध किया गया कि वे जांच अवधि के दौरान भारत में एच एफ आर एम के आयातों के ब्यौरे प्रस्तुत करें जिन पर समीक्षा जांच में विचार किया गया ।

(v) प्राधिकारी ने नियमों के उप-नियम 5(5) के अनुसार समीक्षा जांच की कार्रवाई शुरू करने से पहले नई दिल्ली में सम्बद्ध देश के दूतावास को सूचित किया ।

(vi) प्राधिकारी ने 2.7.2001 को एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की । मौखिक सुनवाई में भाग लेने वाली पार्टियों से मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित रूप में दर्ज करने का अनुरोध किया गया । पार्टियों से प्रतिपक्षी पार्टियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की प्रतियां लेने की सलाह दी गई और उनका खंडन/उत्तर देने का अनुरोध किया गया था ।

(vii) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंशों वाली फाइल को सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध रखा और उसे किसी भी हितबद्ध पार्टी द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रखा ।

(viii) उपरोक्त नियमों के नियम 16 के अनुसार इन निष्कर्षों के लिए विधारित अनिवार्य तथ्यों/आधार को 16.9.2001 को ज्ञात हितबद्ध पार्टियों के समक्ष प्रकट किया गया था और उन पर मिली टिप्पणियों पर भी इन निष्कर्षों में उस सीमा तक विचार किया गया है जहां तक वे संगत हैं और इस मामले पर प्रभाव डालते हैं ।

(ix) प्राधिकारी ने सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भारत में एच एफ आर एम के सभी ज्ञात आयातकों (जिनके ब्यौरे याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) को भेजी और उन्हें लिखित रूप में अपने विचार इस पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर प्रस्तुत करने की सलाह दी ।

(x) प्राधिकारी ने पूर्वकृत नियम 6(3) के अनुसार याचिका की एक प्रति ज्ञात निर्यातकों और संबद्ध देश के दूतावास को भेजी । याचिका की एक प्रति अन्य हितबद्ध पार्टियों को भी अनुरोध करने पर उपलब्ध कराई गयी ।

(xi) प्राधिकारी ने सम्बद्ध सूचना प्राप्त करने के लिए नियम 6(4) के अनुसार सम्बद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली भेजी:-

1. मै0 याइना निगंबो इंटरनेशनल कोआपरेशन ग्रुप कंपनी लि0, चीन
2. मै0 झेजियान डॉगयांग मैगनेटिक इंटरप्राइज ग्रुप कंपनी इंडस्ट्री जोन
3. मै0 चाइना इंटरनेशनल इलैक्ट्रॉनिक्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट संघाई कंपनी, चीन
4. मै0 घाइना नेशनल इलैक्ट्रॉनिक्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट शेनझेन कंपनी
5. मै0 घाइना ग्रेटवाल, चीन
6. मै0 ओ.के. गिलुमल एंड वाट्सुल्ट, हांगकांग
7. मै0 डॉगयांग मैगनैटिक इंटरप्राइज ग्रुप कारपोरेशन, चीन
8. मै0 जयाहर, 37-41, शान मी स्ट्रीट, फ्लॉटन शाटिन, हांगकांग

किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने प्रश्नावली/अधिसूचना का जवाब नहीं दिया था ।

तथापि, मशीनरी तथा इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के आयात और निर्यात से संबंधित चाइना चैम्बर ऑफ कॉर्मस ने दिनांक 14.9.2001 के प्रकटन विवरण और मै0 चाइना नेशनल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ज़िजियांग कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई उत्पादन लागत के बारे में जवाब दिया है।

XII) नई दिल्ली में संबद्ध देश के दूतावास को भी नियम 6(2) के अनुसार समीक्षा जांच आरंभ होने की सूचना दे दी गयी थी और उनसे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों से निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली भरकर भेजने का आग्रह करने का अनुरोध किया गया था। निर्यातकों को भेजे गए पत्र, याचिका और प्रश्नावली की प्रति, ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की सूची सहित दूतावास को भी भेजी गयी थी।

XIII) नियम 6(4) के अनुसार आश्यक सूचना मंगाने के लिए सम्बद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/उपयोक्ता संघों को एक प्रश्नावली भेजी गयी थी:-

1. श्री नरेश उप्पल, दिल्ली
2. मै0 प्रिंस इलैक्ट्रॉनिक्स, दिल्ली
3. मै0 जी. एम. ओवरसीज, नई दिल्ली
4. नै0 एस के ट्रेडिंग, दिल्लाल्ल
5. मै0 राम कृष्ण सेल्स कारपोरेशन, दिल्ली
6. मै0 जे आर सी इंडस्ट्रीज, मुम्बई
7. मै0 अंकित इलैक्ट्रॉनिक्स, दिल्ली
8. मै0 गुडविल इलैक्ट्रॉनिक्स
9. मै0 गौरव इलैक्ट्रॉनिक्स दिल्ली
10. मै0 रोलेट इंडस्ट्रीज, दिल्ली
11. मै0 एस मेहता एंड कंपनी, मुंबई
12. मै0 कलवार एक्सपोर्ट, मुम्बई
13. मै0 सलोरा इंटरनेशनल, नई दिल्ली
14. मै0 आहुजा रेडियो, नई दिल्ली
15. मै0 करीसमैटिक साउंड्स, नई दिल्ली
16. मै0 मैगनेट यूज़र्स एसोसिएशन, नई दिल्ली

निम्नलिखित आयातकों/उपयोक्ता संघों द्वारा प्रश्नावली/अधिसूचना का उत्तर प्रस्तुत किया

गया था:-

1. मै0 सलोरा इंटरनेशनल (स्ट्रेटेजिक लॉ ग्रुप द्वारा)
2. मै0 आहुजा रेडियो (स्ट्रेटेजिक लॉ ग्रुप द्वारा)
3. मै0 करीसमैटिक साउंड्स (स्ट्रेटेजिक लॉ ग्रुप द्वारा)

4. मै0 मैग्नेट उपयोक्ता एसोसिएशन्स

5. मै0 जे आर सी इंडस्ट्रीज, मुम्बई

XIV) क्षति और सम्बद्ध वस्तु के आयातों के बारे में घरेलू उत्पादकों अर्थात् मै0 डीजीपी हिनोडे इंडस्ट्रीज लि0 और मै0 जी पी इलैक्ट्रानिक्स लि0 से सूचना मांगी गई थी।

XV) सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जी ए ए पी) के आधार पर भारत में एच एफ आर एम श्रेणी की इष्टतम उत्पादन लागत तथा माल को बनाने और बेचने की लागत का हिसाब लगाने के लिए घरेलू उद्योग के लिए लागत जांच भी की गई।

XVI) ***** यह चिह्न अधिसूचना में एक हितबद्ध पार्टी द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना तथा नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उसे ऐसा माने जाने का द्योतक है;

XVII) समीक्षा जांच 1.4.1999 से 30.6.2000 अर्थात् समीक्षा हेतु जांच की अवधि (पी ओ आई) तक के लिए की गई थी।

xx. याधिकारकर्ताओं, निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पार्टियों के विचार और प्राधिकारी द्वारा उनकी जांच

विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर प्रकटन विवरण पत्र में चर्चा की गई है। प्रकटन विवरण पत्र के जवाब में उठाए गए मुद्दों पर नीचे दिए गए संगत पैराग्राफों में उस सीमा तक विचार किया गया है जहां तक वे नियमानुसार संगत हैं और जहां तक वे इस मामले पर प्रभाव डालते हैं। हितबद्ध पार्टियों द्वारा उठाए गए तकीं की जांच की गई और जहां कहीं उचित समझा गया है नीचे संगत पैराग्राफों में उन पर विचार किया गया है।

(क) विद्याराधीन उत्पाद और समान वस्तु

- मैसर्स डीजीपी हिनोडे इंडस्ट्रीज लि., पुणे और मैसर्स जी.पी. इलैक्ट्रानिक्स लि., नाशिक ने निम्नलिखित अनुरोध किया है:-
 - विचाराधीन उत्पाद हार्ड फेराइट रिंग मैग्नेट्स है जिसका इस्तेमाल लाउडस्पीकरों/पी ए सिस्टम/दूर-संचार और विभिन्न अन्य उपयोगों में किया जाता है।
 - स्ट्रोंटियम ग्रेड एचएफआरएम अधिक कीमती हैं और इसका उपयोग उच्च अनुप्रयोगों में किया जाता हैं तथा भारतीय बाजार में इसका प्रयोग 1% से भी कम है। बेरियम ग्रेडों में आयातकों द्वारा 30% से 40% तक जो लागत भिन्नता दर्शायी गयी है, वह हास्यास्पद है। हमने हार्ड फेराइट उत्पाद को मैग्नेट्स और मोटर मैग्नेट्स के सम्बन्ध वस्तु नहीं माना है।
 - घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त परिकलित लागत बेरियम रिंग मैग्नेट्स की है और स्ट्रोंटियम मैग्नेट्स की लागत बिल्कुल भिन्न है।
- मैसर्स स्ट्रेटेजिक लॉ ग्रुप जो (मैसर्स सलारा इनटरनेशनल, मैसर्स आहुजा रेडियो और मैसर्स करिस्मैटिक साउन्ड्स) का प्रतिनिधित्व करता है और मैग्नेट यूजर्स एसोसिएशन ने निम्नलिखित अनुरोध किया है:-
 - एचएफआरएम के अनेक उपयोग हैं और ये भिन्न-भिन्न गुणवत्ता वाले हैं। ये वाई४८ से लेकर वाई 35 के ग्रेड में उपलब्ध हैं और इनकी लागूत अलग-अलग है। याचिकाकर्ताओं ने बेरियम और स्ट्रोंटियम दोनों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की मांग की है जिनकी लागत मूलरूप से भिन्न है। इनके अलावा, हार्ड फेराइट मैग्नेट्स गोलाकार से भिन्न आकारों में भी आता हैं जो जांच के दायरे में नहीं आता है। वाई 8 और वाई 35 ग्रेड के बीच लागत में भिन्नता 35-45% तक है। सामान्य तौर पर स्ट्रोंटियम फेराइट द्वारा निर्मित एच एफ आर एम बेरियम फेराइट द्वारा निर्मित एचएफआरएम से लगभग 20-25% तक अधिक कीमती है।

(ii) वस्तुतः एचएफआरएम-1 (मूल जांच) में माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विशेषरूप से स्ट्रोंटियम एचएफआरएम को शामिल नहीं किया था। इस प्रकार, इस समीक्षा याचिका में विचाराधीन उत्पाद के दायरे को बढ़ाना अब खुला नहीं है।

(iii) किसी परिभाषा से कोई समीक्षा नई जांच से अधिक सीमित हो सकती है और इसे केवल उन मानदण्डों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए जो पहले से अब बदल गए हैं। मूल जांच (एचएफआरएम-1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह बात स्वीकार की थी कि चीनी उत्पादकों को 25% लागत का लाभ है जो याचिकाकर्ताओं ने स्वयं स्वीकार किया था। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जो विधि अपनाई गई थी उसे घरेलू उद्योग द्वारा माननीय सीगैट के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी। अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी इस अवस्था में संख्याओं में आए परिवर्तन की ही जांच कर सकते हैं और इसे आधार परिवर्तित करने तक सीमित किया जाएगा।

प्रकटीकरण के उत्तर में मैसर्स स्ट्रोटेजिक लॉ ग्रुप (एसएलजी) ने निम्नलिखित अनुरोध किया है:-

(क) यह बात नोट करना महत्वपूर्ण है कि याचिका-कर्ताओं ने स्वयं अपने आवेदन में वाई-25 ग्रेड के अनुरूप तकनीकी विनिर्देशन दिए हैं। इसका स्पष्ट तात्पर्य होगा कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा समीक्षा प्रयोजनार्थ वाई-25 तक सीमित है। अतः समीक्षा को केवल वाई-25 ग्रेड तक ही सीमित किया जाना चाहिए और इसका विस्तार किसी अन्य ग्रेड तक नहीं किया जा सकता है।

(ख) याचिकाकर्ताओं ने इस समीक्षा में स्ट्रोंटियम ग्रेड को शामिल करने की मांग की थी। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि वे स्ट्रोंटियम ग्रेड एचएफआरएम के खिलाफ कथित पाटन के मामले को वापस ले रहे हैं।

(ग) मैग्नेट के विभिन्न ग्रेडों के बीच कीमत संबंधी अंतर के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है, वह हास्यास्पद है। यह कहा जा सकता है कि विभिन्न बेरियम ग्रेडों में जो कीमत भिन्नता है वह 30% से 40% तक की सीमा तक है उसका समर्थन मैसर्स सलोरा एण्ड

आहुजा रेडियोज द्वारा आयातित वाई-25 मैग्नेट्स के आंकड़ों से किया गया है।

मैसर्स करिस्मति साउंड्स द्वारा आयातित वाई-20 ग्रेड के आयात आंकड़े यह प्रदर्शित करने हेतु दिए गए थे कि वाई-25 और वाई-20 ग्रेड के बीच कीमत भिन्नता 15 से 20% तक है। यह स्पष्ट है कि वाई-8 और वाई-15 ग्रेड वाई-25 ग्रेड और वाई-30 ग्रेड से काफी सस्ते होंगे और वाई-35 ग्रेड वाई-25 ग्रेड से काफी अधिक महंगा होगा। इस प्रकार वाई-35 और वाई-8 ग्रेडों के बीच यह अंतर लगभग 40% होगा।

(घ) याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई यह दलील कि स्ट्रोंटियम ग्रेड मैग्नेट्स भारतीय बाजार के 1% से कम का बना हुआ है, पूर्णतः भ्रामक है, बल्कि इसका 15% से 20% तक बाजारी उपयोग हैं जबकि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने एनआईपी के परिकलन के प्रयोजनार्थ केवल 1% पर छोड़ी विचार किया है, इससे पूर्णतः गलत और अधिक एनआईपी प्रदान होगी। हम निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करेंगे कि एनआईपी के परिकलन के प्रयोजनार्थ अपनी - लागत बढ़ाने हेतु घरेलू उद्योग द्वारा जो प्रयास किया ~~माया है~~ वह सफल नहीं हुआ है। हम अनुरोध करते हैं कि हमें एनआईपी परिकलन से संबंधित प्रकटीकरण विवरण के अगोपनीय अंश उपलब्ध कराए जायं ताकि हम इस पर अपनी टिप्पणियाँ दे सकें।

(ड.) यह बात नोट करते हुए कि समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद बदला नहीं है, उपभोक्ता उद्योग यह कहना चाहता है कि केवल वाई-25 ग्रेड के रिंग में मैग्नेट्स के इतर मैग्नेटों को पाटनरोधी शुल्क के दायरे से बाहर रखा जाय।

(च) तुलना के प्रयोजनार्थ सभी आकारों को एक समान अंक तक घटाने के संदर्भ में उपभोक्ता उद्योग अनुरोध करता है कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात पर विचार करते हैं कि ग्रेडों के आधार पर जो लागत भिन्नता है वह इसके लिए उत्तरदायी नहीं है और प्रत्येक ग्रेड को पृथक-पृथक माना जाय। इस तथ्य के होते हुए भी कि निर्यातकों से कोई सहयोग नहीं मिला है, आयातकों ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वे इस विश्लेषण के लिए पर्याप्त होने चाहिए। चीन के निर्यातकों ने माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को वाई-25 ग्रेड मैग्नेट्स के उत्पादन लागत संबंधी

आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जिन्हें उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के एक भाग के रूप में हिसाब में लिया जाना चाहिए और आंकड़ों पर चीन की परिकलित लागत पर विचार कर, यदि आवश्यक हुआ तो, इसकी जांच करवाई जा सकती है।

3. प्राधिकारी द्वारा जांच

प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोधों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान जांच केवल एक समीक्षा है, दिनांक 12.7.99 के अंतिम निष्कर्षों के पैरा ग (3) में यथा प्रदत्त विचाराधीन उत्पाद के बारे में जांच के दायरे की पुष्टि करना उचित समझते हैं। विचाराधीन उत्पाद लाउडस्पीकरों, पब्लिक एडरैस सिस्टम, मैग्नेटिक एसेम्बलीज इत्यादि में प्रयुक्त हाई फेराइट रिंग है। यह उत्पाद बेरियम कारबोनेट और स्ट्रोंटियम कारबोनेट इत्यादि से बनाया जाता है। रिंग मैग्नेट्स बाह्य परिधि अनुसार विभिन्न आकारों के होते हैं जो 22 मि.मी से 280 मि.मी तक के होते हैं और भीतरी परिधि 12 मि.मी से 180 मि.मी तक की होती है और मोटाई 12 मि.मी. से 180 मि.मी. तक की होती है जो अपेक्षित प्रयोग के आधार पर निर्भर करती है। एच एफ आर एम का वर्गीकरण सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची- 1 के सीमाशुल्क शीर्ष 8505 के तहत किया गया है। बिना मैग्नेट के रूप में आयातित संबद्ध वस्तु की जांच के दायरे में शामिल है।

(ख) घरेलू उद्योग

प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता की हैसियत के बारे में किसी हितबद्ध पक्ष ने कोई अनुरोध नहीं किया है। प्राधिकारी यह बात भी नोट करते हैं कि जिन पाँच घरेलू उत्पादकों ने पूर्ववर्ती याचिका दायर की थी, उनमें से तीन इकाईयाँ बन्द हो गई हैं और इस समय देश में एचएफआरएम के केवल दो उत्पादक अर्थात् मैसर्स डीजीपी होनोडे इंडस्ट्रीज लि., पुणे और मैसर्स जी.पी.इलैक्ट्रोनिक्स लि., नासिक हैं जो नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग बनते हैं।

(ग) पाटन, सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

प्राधिकारी यह बात नोट करते हैं कि जांच आरंभ करने के जबाब में विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं-

1. मैसर्स डीजीपी हिनोडे इंडस्ट्रीज लि., पुणे और मैसर्स जी.पी. इलैक्ट्रोनिक्स लि., नासिक ने निम्नलिखित अनुरोध किया है:-

(i) हम पहले भारतीय पैमाने की तुलना में आटोमेशन, सस्ती लेबर, सस्ती बिजली, उच्च उत्पादकता और बिक्रियों की मितव्ययिता के कारण चीनी उत्पादकों को मिलने वाली लागत संबंधी लाभ पर सहमत हो गए थे। चूंकि चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाता है, इसलिए चीन में घरेलू कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण की अपेक्षा नहीं है।

इस प्रकार चीन में घरेलू कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करते समय पहले दिए गए लाभ इस मामले में अब संगत नहीं रह गए हैं।

चूंकि चीन के निर्यातकों ने सहयोग न करने का निर्णय लिया है इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना बन जाती है। हमारा यह भी अनुरोध है कि सीगैट के निर्णय में केवल निर्यातक ही सामान्य मूल्य को चुनौती दे सकता है और आयातक को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है।

(ii) हमने निर्यात कीमत के साक्ष्य के रूप में निजी एजेंसियों से एकत्रित आयात आंकड़ों के आधार पर किए गए आयात सौदों से निर्यात कीमत निर्धारित की है। ये आंकड़े डी जी सी आई एंड इस से एकत्र नहीं किए जा सके क्योंकि अध्याय 8505.19 के अंतर्गत वर्गीकृत उनके आंकड़ों में कई किस्मों की मैगनेट्स हैं। हमने निर्यात कीमत **xxxxx ₹0/किं०** ग्रा० निर्धारित की है। हमारा निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह हितबद्ध पक्षों से नगों की संख्या तथा आयातों के तदनुसारी निवल भार का ब्लौरा देते हुए अपने आयातों के संपूर्ण ब्लौरे प्रस्तुत करने के लिए करें। उन आयातकों, जिन्होंने आमेलन की प्रक्रिया अपनाई है और इस प्रकार पाटनरोधी शुल्कों का अवक्षन किया है, की बजाय याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई सूचना पर भरोसा किया जा सकता है।

(iii) स्वचालन, सस्ते श्रमिक एवं विद्युत, उच्च उत्पादकता तथा बड़े पैमाने पर बद्धतों जैसे कारकों पर भिन्न-भिन्न प्रकार की इमदादों को ध्यान में रखे बगैर लागत लाभ प्रदान किए गए थे । पाटनरोधी नियम, 44/99-सी.शु.गै.टै. दिनांक 15.7.1999 तथा 27/2001-सी.शु.गै.टै.-31/5/2001 के अनुसार चीन को प्रदत्त लागत लाभ अब संगत नहीं रह गए हैं । भारत को पूर्व में प्रतिनिधि देश के रूप में माना जाता था । यूंकि चीनी निर्यातकों ने सहयोग नहीं किया है इसलिए पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-I पैरा 7 तथा 8 के प्रावधानों को सामान्य मूल्य के निर्धारण लागू न किया जाए ।

(iv) कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए समुद्री भाड़, कमीशन, बीमा, स्वदेशी परिवहन और पत्तन खर्चों के समायोजनों पर विचार किया जाए ।

प्रकटन विवरण के उत्तर में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

(i) पूर्ववर्ती निष्कर्षों से हटकर प्राधिकारी ने चीन जैसी गैर बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के संबंध में यर्तमान कानून की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव किया है ।

(ii) एक ओर प्रधिकारी का यह कहना है कि, "यूंकि यह एक समीक्षा जांच है इसलिए पूर्ववर्ती निष्कर्षों में अपनायी गई प्रक्रिया को अपनाना तथा लागत लाभ संबंधी समायोजनों पर विचार करने का प्रस्ताव है, और दूसरी ओर उसने कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें लेकर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने की उक्त प्रक्रिया को बदल दिया है जो कि स्पष्ट रूप से परस्पर विरोधी है ।

(iii) यह एक सुस्थापित कानून है कि हालांकि निर्यातकों को सामान्य मूल्य के निर्धारण पर प्रश्न उठाने का अधिकार है, तथापि आयातकों/उपयोक्ताओं के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है । हालांकि प्राधिकारी एक ओर तो यह कहते हैं कि निर्यातक ने जांच में सहयोग नहीं किया है किन्तु दूसरी ओर वे आयातकों/उपयोक्ता द्वारा दिए गए इन

तकाँ को स्वीकार करते हैं कि पूर्ववर्ती निष्कर्षों में प्रदत्त 25% के लागत लाभ को कायम रखा जाना चाहिए। प्राधिकारी का यह दृष्टिकोण इस मामले में एकदम प्रतिकूल है। (सीगेट का निर्णय संदर्भ सं. ए आई आई जी एम ए बनाम डी ए 2000 (119)(ई.एल.टी.) 333)

(iv) प्राधिकारी ने यह उल्लेख किया है कि पाटनरोधी नियमों के नियम 23 के अनुसार समीक्षा जांच की गई है। नियम 23 में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख है कि:

‘ समीक्षा के मामले में नियम 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 तथा 20 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

पाटनरोधी नियमों के अनुबंध 1 में दिनांक 15.7.99 तथा 31.5.2001 की अधिसूचनाओं (जैसा कि प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है) द्वारा संशोधन किए गए हैं। सामान्य मूल्य का निर्धारण करते समय प्राधिकारी ने इस तथ्य की पूरी तरह से उपेक्षा कर दी है कि चीन जैसी गैर बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया पाटनरोधी नियमों के अनुबंध 1 के पैराग्राफ 7 तथा 8 में स्पष्ट रूप से दी गयी है (ब्यौरे नीचे पैरा 5 में दिए गए हैं) जैसी कि यह आज भी लागू है और इस प्रकार 25% लागत लाभ जारी रखने का इसका प्रस्ताव नियम 23 के स्पष्टतः प्रतिकूल है जिसमें यह उल्लेख है कि ये प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे और इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण इस विषय में वर्तमान कानून के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

इस संबंध में हम नियम 10 के प्रावधानों का भी उल्लेख करना चाहेंगे जो सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन से संबंधित हैं। नियम 23 के प्रावधानों के अनुसार सामान्य मूल्य का पुनः निर्धारण नियम 10 के अंतर्गत करना होता है और

अंतिम निष्कर्षों के समय पर प्रचलित कानून एवं इससे संबंधित अन्य कारकों पर विचार करते हुए इसका निर्धारण किया जाना चाहिए ।

(v) चीन को एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाता है और पाटनरोधी नियमों के अनुबंध 1 के संशोधित पैराग्राफ 7 और 8 के अनुसार सामान्य मूल्य का आकलन किया जाना है । पैराग्राफ 7 के अनुसार सामान्य मूल्य का निम्नानुसार निर्धारण किया जाना चाहिए:-

- क. किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर, अथवा ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत के आधार पर, अथवा
- ख. यदि ऐसा करना संभव न हो तो समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तविक रूपसे संदत्त अथवा संदेय कीमत, जिसे यदि आवश्यक हो समुचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित किया गया हो, सहित किसी अन्य यथोचित आधार पर ।

पाटनरोधी नियमों के अनुबंध 1 के पैराग्राफ 8 के अनुसार जब तक चीन में निर्यातक द्वारा लिखित में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर यह नहीं दर्शाया जाता है कि उनकी अर्थव्यवस्था में बाजार स्थितियां विद्यमान हैं, तब तक सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए पाटनरोधी नियमों के अनुबंध 1 के पैराग्राफ 7 में ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया के सिवाय और किसी प्रक्रिया को अपनाया नहीं जा सकता है । इस प्रकार हमें कच्चे माल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के तरीके पर कझी आपत्ति है जोकि मात्र एक अनुमान ही होगा । जब नियमों के तहत भारत में वास्तविक रूप से संदत्त अथवा संदेय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने की अनुमति है तब अनुमानित आधार पर सामान्य कीमत का निर्धारण क्यों किया जाना चाहिए ।

इसके अलावा, कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने से भारित औसत सामान्य मूल्य की शर्त पूरी नहीं होती है जैसी कि कानून में व्यवस्था है और प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव किया गया है। भारित औसत सामान्य मूल्य का निर्धारण जांच की समग्र अवधि के दौरान विद्यमान उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए किया जाता है जिसका यदि वास्तविक उत्पादन से भाग कर दिया जाए तो भारित औसत उत्पादन लागत और इस प्रकार भारित औसत सामान्य मूल्य निकल आता है।

(vi) प्रकटन विवरण में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्राधिकारी का वह प्रक्रिया अपनाने और लागत लाभ संबंधी समायोजनों (अर्थात् 25%) पर विचार करने का प्रस्ताव है जैसाकि पूर्ववर्ती निष्कर्षों में किया गया है। चूंकि चीन के निर्यातकों ने जांच प्रक्रिया में भाग नहीं लेने का फैसला किया है और उन्हें गैर बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाता है और इसलिए पूर्ववर्ती निष्कर्षों में दिए गए 25% के लागत लाभ पर इस समय निम्नलिखित कारणों से विचार नहीं किया जा सकता है:-

1. सामान्य मूल्य का निर्धारण केवल दिनांक 15.7.99 के पाटनरोधी नियम 44/99-सी.शु.गै.टै. तथा दिनांक 31.5.2001 के पाटनरोधी नियम 27/2001-सी.शु. गै.टै. के तहत किए गए पाटनरोधी नियमों में किए गए संशोधनों के अनुसार पाटनरोधी नियमों के अनुबंध 1 के पैराग्राफ 7 के अनुसार ही किया जा सकता है।
2. जांच की अवधि परिवर्तित हो गयी है और इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुमानित आधारकी बजाय परिवर्तित जांच अवधि के दौरान वास्तविक उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए पाटनरोधी नियमों के अनुबंध 1 के पैराग्राफ 7 और 8 के अनुसार किया जाना चाहिए।

3. धीन जैसी किसी गैर बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन की लागत को कम करने वाले उत्पादन के विभिन्न मापदण्ड विभिन्न प्रकार की सरकारी इमदादों के कारण हैं न कि पहले उल्लिखित उत्पादकता कारकों के कारण ।

अतः हम प्राधिकारी से अपने प्रस्ताव में आवश्यक परिवर्तन करने का अनुरोध करते हैं क्योंकि अपनाए जाने के लिए प्रस्तावित प्रक्रिया न तो नियम 23 के प्रावधानों और न ही पाटनरोधी जांच की भावना के अनुसार है जिसे केवल अनुमानों के बजाय सर्वोन्नतम उपलब्ध सूचना के आधार पर विधार किए जाने वाले वास्तविक तथ्यों पर आधारित होना जरूरी है ।

निर्यात कीमत

प्राधिकारी ने ऐसे सभी आयात सौदों का भारित औसत निकालने का प्रस्ताव किया है जिनके ब्यौरे समस्त खोतों से उपलब्ध हैं । हम प्राधिकारी का ध्यान हमारे दिनांक 23 जुलाई, 01 के पत्र की ओर दिलाना चाहेंगे जिसमें हमने जांच की अवधि के दौरान कुछेक आयात सौदों के ब्यौरे दिए हैं ।

इन सौदों का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि पर्याप्ततः भिन्न-भिन्न कीमतों पर एक ही समय में एक ही देश से एक ही उत्पाद का आयात किस प्रकार किया जा सकता है । ऐसे सौदों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सामान्यस्वरूप में हुआ नहीं माना जा सकता है । हम प्राधिकारी से इन पार्टियों द्वारा दिए गए समर्थनकारी दस्तावेजों और साक्ष्यों की जांच करने का अनुरोध करते हैं ताकि भारित औसत निर्यात कीमत निकालने के लिए उन पर विधार करने से पहले उनकी प्रामाणिकता सुनिश्चित की जा सके अथवा अन्यथा उन्हें पूरी तरह से नकार दिया जाना चाहिए ।

2. मैं0 स्ट्रेटेजिक ला ग्रुप (मैं0 सलोरा इंटरनेशनल, मैं0 आहूजा रेडियो तथा मैं0 करिशमैटिक साउंड्स का प्रतिनिधित्व करने वाला) तथा मैगनेट यूजर्स एशोसिएशन ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं-

- (i) याचिकाकर्त्ताओं ने एक सामान्य मूल्य का आंकलन किया है और वे एक समान दर से पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक आधार रहित और अविश्वसनीय कम निर्यात कीमत का दावा कर रहे हैं।
- (ii) विभिन्न अनुप्रयोगों के निमित्त विभिन्न किस्मों और गुणवत्ता के मैगेनेटों को एक साथ लिया जाना इस विषय के व्यवहारों और विधि शास्त्र के अनुसार नहीं है। उचित तुलना के लिए अपेक्षित है कि तुलना को किस्मावार आधार पर किया जाना आवश्यक है औरऐसा करते हुए उन सभी कारकों को, जो कीमत की तुलनीयता को प्रभावित करते हैं, ध्यान में लिया जाना चाहिए। इसलिए यह विधिक और तार्किक दृष्टि से उचित होगा यदि पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन की गणना करते समय कच्ची सामग्रियों की कम से कम उत्पादन लागत को और इसकी भिन्न भिन्न कीमतों को प्रदर्शित किया जाए। इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि घरेलू उद्योग के लिए उत्पादन लागत की गणना करते समय विभिन्न प्रकार के उत्पादों के आकार, उनकी गुणवत्ता और ग्रेडों को आवश्यकतानुसार ध्यान में लिया जाना चाहिए।
- (iii) आयातकर्त्ताओं द्वारा चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत प्रदान की गई है।
- (iv) याचिकाकर्त्ताओं द्वारा दिए गए आयात आंकड़े गलत एवं प्रतिकूल हैं, जिन्हें यातो दोहराया गया है या जो जांच अवधि से संबंधित नहीं है।

(v) मैग्नेट उपयोक्ता एसोसिएशन ने लगभग 724.6 मीट्रिक टन के आयात आंकड़े इकट्ठे किए हैं जिनकी निर्दिष्ट प्राधिकारी लेखा परीक्षा कर सकता है।

प्रकटन विवरण के जवाब में निम्नलिखित निवेदन किए गए हैं-

(क) उपभोक्ता उद्योग नोट करते हैं कि दिनांक 31.5.2001 की अधिसूचना में यथा-उल्लिखित 'बैर-बाजार अर्थव्यवस्था' के सिद्धांत लागू नहीं होंगे क्योंकि इस मामले की शुरूआत नियमों में संशोधनसे पूर्व हुई थी। इसलिए, हम यह निवेदन करते हैं कि निर्दिष्ट प्राधिकारी कृपया उक्त अधिसूचना का कोई संदर्भ न लें।

(ख) इसके अलावा, हम समझते हैं कि स्वीकृत लागत लाभ सहित एचएफआरएम-1 में यथा-प्रयुक्त सिद्धांतों को अपनात हुए लागत निर्धारण की कार्य-पद्धति अपरिवर्धित बनी रहेगी। हम यह भी समझते हैं कि केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित कच्ची सामग्री की कीमतों और लागतों को लागू किया जाएगा। अनुरोध है कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा एचएफआरएम-1 से भिन्न ऐसे समुचित समायोजन, जो उपभोक्ता उद्योग के प्रतिकूल हो, तंब तक न किए जाएं जब तक कि आयातकों द्वारा प्रकटन न किया गया हो।

(ग) यह भी नोट किया जाता है कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी आयातकों एवं राजस्व विभाग(सीमा-शुल्क प्राधिकारी) द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर विश्वासकरेंगे। यह माना जाता है कि सीमा-शुल्क प्राधिकारियों के आंकड़ों को डीजीसीआईएडएस द्वारा पुनः प्रस्तुत किया जाता है।

(घ) अनुरोध है कि आंकड़ों में भिन्नता होने की स्थिति में उनका खुलासा आयातकों को करना जरूरी है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

सामान्य मूल्य

धारा 9क(1)(ग)के तहत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है:-

- (i) सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तुओं के लिए उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियम के अनुसार यथानिर्दिष्ट तुलनात्मक मूल्य जबकि ऐसी वस्तु निर्यातक देश या क्षेत्र में उपभोग के लिए आशयित हो; या
- (ii) जब व्यापार के सामान्य रूप में निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में समान वस्तु की बिक्री न हो या जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में विशेष बाजार स्थिति या बिक्री की कम मात्रा के कारण ऐसी बिक्री से उचित तुलना नहीं की जा सकती, तब सामान्य मूल्य इनमें से कोई एक होगा;
- (क) निर्यातक देश या क्षेत्र से किसी उचित तीसरे देश से आयात किए जाने पर समान वस्तु का उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथा निश्चित तुलनात्मक प्रतिनिधि मूल्य; या
- (ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथा निश्चित प्रशासनिक बिक्री और सामान्य लागतों एवं लाभों के लिए उचित वृद्धि के साथ वस्तु मूल के देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत;

बशर्ते कि वस्तु का आयात जब मूलता के देश से भिन्न अन्य किसी देश से किया गया हो तथा जहां वस्तु निर्यात के देश से केवल गुजरी हो या ऐसी वस्तु निर्यात के देश में उत्पादित नहीं होती हो या निर्यात के देश में उसका कोई तुलनात्मक मूल्य नहीं हो तो इसके सामान्य मूल्य का निर्धारण मूलता के देश में इसके मूल्य के संदर्भ में किया जाएगा ।

प्राधिकारी उपरोक्तानुसार विभिन्न हितबद्ध पार्टीयों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट करते हैं । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि किसी भी निर्यातक ने निर्धारित प्रश्नावली में उत्तर के जरिए सहयोग नहीं दिया है यद्यपि, चीन नेशनल इलैक्ट्रोनिक्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जिजियांग कंपनी ने वर्ष 1999-2000 के लिए एचएफआरएम के वाई-25 ग्रेड की उत्पादन लागत प्रस्तुत की थी न कि जांच

अवधि के लिए । यह सूचना भी मांगे गए उत्तर के प्रपत्र के अनुसार नहीं है और पूरी भी नहीं है । अतः इन परिस्थितियों में प्राधिकारी ने नियम 6(8) के अनुसार सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य का आकलन किया । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि चीन सहित कुछेक देशों के संबंध में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधानों के बारे में 31.5.2001 की सी.शु. अधिसूचना के तहत अधिसूचित संशोधन को ध्यान में रखते हुए निर्यातक को लागत संबंधी कोई लाभ दिए बिना भारत में संदत्त/संदेह संबद्ध वस्तु की कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार कियचाप जाना चाहिए क्योंकि यह लाभ चीन में उपलब्ध इमदाद के कारण मिलत हैं और यह कि कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का संदर्भ लेने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि भारत में संदेह कीमत ही वह कीमत है जो संशोधित नियमों के अनुसार प्रसांगिक होती है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि इस प्रकार का कोई दृष्टिकोण न्यायाचित है क्योंकि चीन के किसी भी निर्यातक ने सहयोग नहीं किया है ।

आयातकों अर्थात् मै0सलौरा इंटरनेशनल, मै0 आहुजा रेडियो और मै0 करिशमैटिक साउंड्स का प्रतिनिधित्व करने वाले मै0 स्ट्रेटेजिक लॉ ग्रुपने उल्लेख किया है कि 31.5.2001 की सी.शु. अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता । इन अनुरोधों की जांच के बाद प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यूंकि चीन जनवादी गणराज्य के किसी भी निर्यातक/उत्पादक से प्रश्नावली के अनुसासर उत्तर नहीं मिला है इसलिए, संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का आकलन सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर करना जरूरी होगा ।

प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यद्यपि पाटनरोधी जांच की शुरुआत पाटनरोधी नियमों में संशोधन से पूर्व की गई थी तथापि, प्राधिकारी द्वारा संशोधित नियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार भी सामान्य मूल्य के आकलन हेतु उचित आधार को

स्वीकार करने का कार्य नियमानुसार सुसंगत है । अतः प्राधिकारी ने उचित आधार अपनाया है जिसमें सामान्य मूल्य के आकलन हेतु याचिकाकर्ता द्वारा पहले किए गए दावे के अनुसार लागत संबंधी लाभ और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर कच्ची सामग्री के संबंध में समुचित समायोजन शामिल होंगे । प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच समीक्षा जांच होने के नाते पूर्ववर्ती जांच में चीन जनवादी गराज्य के निर्यातकों को उत्पादन लागत पर 25% तक दिए गए समायोजन भी । स्वीकार करने के लिए उचित हैं क्योंकि याचिकाकर्ता उसे वापस लेने हेतु सी उचित आधार/साक्ष्य के विरोध में नहीं है । अतः प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग रा उपलब्ध कीगई संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और जांच अवधि में अंतर्राष्ट्र कीमत पर विचारित कच्ची सामग्री के साथ जांच द्वारा किए गए सत्यापन और : श्री सामग्री से भिन्न लागत पर 25%लागत लाभ पर विचार करते हुए सामान मूल्य का आकलन किया है । जांच अवधि में संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का भ. औसत सामान्य मूल्य ***** रु०/कि.ग्रा. बनता है ।

निर्यात कीमत

प्राधिकारी याचिकाकर्ता, मै० स्ट्रैटेजिक लॉ ग्रुप (एसएलजी) और मै० मैगनेटिक उपयोक्ता एसोशिएशन द्वारा संबद्ध वस्तु हेतु आयात संबंधी आंकड़ों के स्रोतों को स्वीकार करने के बारे में किए गए अनुरोधों को नोट करते हैं । प्राधिकारी ने मै०सलौरा इन्टरनेशनल, मै० आहुजा रेडियो और मै० करिशमैटिक साउंड्स द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन किया है । याचिकाकर्ताओं द्वारायह उल्लेख किया गया है कि मै०करेशमैटिक साउंड्स ने 9.2.2000 और 8.3.2000 को संबद्ध वस्तु की दो खेपों का उच्च कीमत पर आयात किया है । याचिकाकर्ता ने आयातकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को स्वीकार करने से पूर्व इन आंकड़ों को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था । प्राधिकारी ने इन आयात खेपों से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन कर यह नोट किया है कि ये आयात उन कीमतों

पर किए गए हैं जो अन्य सामान्य निर्यात सौदों से तुलनीय हैं । अतः याचिकाकर्त्ताओं के अनुरोधों को स्वीकार्य नहीं पाया गया । अतः प्राधिकारी ने इन आयातों के संबंध में याचिकाकर्त्ता द्वारा गौण स्रोतों से उपलब्ध किए गए आंकड़ों की उपेक्षा की है और उन्होंने मै०सलौरा इन्टरनेशनल, मै० आहुजा रेडिया और मै० करिशमेटिक साउर्ड्स के संबंध में यथा-सत्यापित आयात संबंधी आंकड़ों को स्वीकार किया है । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि याचिकाकर्त्ता ने तीन गौण स्रोतों अर्थात् वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मुम्बई, वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी ब्यूरो और इम्पैक्स स्टैटिकल सर्वेसिज, मुम्बई से 724 मीट्रिक टन तक संबद्ध वस्तु की आयात कीमतें प्रस्तुत की हैं । प्राधिकारी को सीमा शुल्क और मैसर्स जे.आर.सी. इंडस्ट्रीज से भी आयात संबंधी आंकड़े प्राप्त हुए हैं । प्राधिकारी ने आयात कीमत के आंकलन हेतु सीमा-शुल्क और मै० जे.आर.सी. इंडस्ट्रीज के संगत आंकड़े स्वीकार किए हैं । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि याचिकाकर्त्ता ने संगत आकार और संबद्ध वस्तु, जहां संबद्ध वस्तु का भार 225 मी० टन तक उपलब्ध था, के बारे में आयात संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराए हैं । ऊपर यथा-उल्लिखित भिन्न-भिन्न स्रोतों से प्राप्त आयात संबंधी सभी संगत आंकड़े स्वीकार किए गए हैं । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों में कोई अनन्य शीर्ष नहीं है जैसाकि याचिकाकर्त्ता और अन्य हितबद्ध पार्टियों ने उल्लेख भी किया है । अतः प्राधिकारी डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों का संदर्भ लेना उचित नहीं समझते हैं । जांच अवधि में संबद्ध वस्तु की भारित औसत सी आई एफ कीमत का आकलन *** रु०/कि.ग्रा. किया गया है । कारखाना निर्यात कीमत निकालने के लिए प्राधिकारी ने याचिकाकर्त्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों और आयातकों द्वारा भी उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर समुद्री भाड़, समुद्री बीमा, कमीशन, स्पेशन भाड़ और पत्तन खर्चों के कारण क्रमशः *** , *** , *** , *** रु०/कि.ग्रा. के समायोजनों पर विधार किया है । जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के सभी ग्रेडों की भारित औसत कारखाना निर्यात कीमत *** रु०/कि.ग्रा. बैठती है ।

पाटन मार्जिन

तुलना से संबंधित नियमों में निम्नानुसार प्रावधान है:-

"पाटन का मार्जिन निकालते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के बीच के उचित तुलना करेगा । यह तुलना व्यापार के समान स्तर पर सामान्यतया कारखाना द्वार स्तर पर की जाएगी और यथासंभव उसी समयावधि के दौरान की गई बिक्रियों के संबंध में की जाएगी । जो अंतर कीमत तुलनीयता पर प्रभाव डालते हैं, उनके लिए प्रत्येक मामले में गुण-दोष के आधार पर उचित छूट दी जाएगी । उक्त अन्तर में बिक्री की शर्तें, करधान, व्यापार के स्तर, मात्राएं, भौतिक विशेषताएं तथा अन्य ऐसे अन्तर शामिल हैं, जो कीमत तुलनीयता को प्रभावित करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं"।

प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनसे भारित औसत सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना द्वार पर भारित औसत निर्यात कीमत के साथ की है ।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै0 एसएलजी ने पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए ग्रेड-वार तुलना के लिए अनुरोध किया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि पूर्ववर्ती जांच में पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए भारित औसत का दृष्टिकोण अपनाया गया था । वर्तमान समीक्षा में प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद वही है और यह कि निर्यातक में से किसी भी निर्यातक ने निर्यातकों को भेजी गई निर्धारित प्रश्नावली में ग्रेड-वार उत्तर देने के लिए सहयोग नहीं किया है । प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती शुरूआती जांच में अपनाई गई प्रक्रिया को भी ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम उल्लङ्घन सूचना के आधार पर मौजूदा समीक्षा में पाटन मार्जिन का निर्धारण जांच अवधियों एचएफआरएम के सभी ग्रेडों के भारित औसत सामान्य मूल्य की तुलना एचएफआरएम के सभी ग्रेडों की कारखाना द्वार पर भारित औसत निर्यात कीमत के साथ करके किया है । पाटन मार्जिन निम्नानुसार बैठता है:-

निर्यातक/उत्पादक	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन(%)
चीन जनवादी	***	***	47.44
गणराज्य के सभी			
उत्पादक/निर्यातक			

घ. क्षति, कारणात्मक संबंध और क्षति का निर्धारण

उपरोक्त नियम 11 अनुबंध-II के अंतर्गत जब क्षति के निष्कर्ष पर पहुंचा जाए तो ऐसे निष्कर्ष में, " प्राप्ति आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं की घरेलू बाजार में कीमतों पर उनका प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामकारी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए....." घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण शामिल किया जाएगा । कीमतों पर पारित आयातों ले प्रभाव पर विचार करते समय यह जांच करना जरूरी समझा गया है कि भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में प्राप्ति आयातों से कीमत में महत्वपूर्ण कमी आई है या नहीं अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से काफी हद तक कीमतों में कमी या कीमतों में वृद्धि में रुकावट आई है या नहीं जिसमें अन्यथा काफी हद तक वृद्धि हुई होती ।

भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच के लिए उपर्युक्त नियमों के अनुबंध II (IV) के अनुसार हम उन संकेतकों पर विचार कर सकते हैं, जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रीमात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि ।

विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं-

1. मै0डीजीपी हिनोडे इंडस्ट्रीज लि0 पुणे, और मै0 जी0 पी0इलैक्ट्रोनिक्स लि0, नासिक ।

(i) समीक्षा पाटन-रोधी नियमों के नियम 23 के अनुसार की जानी चाहिए । समीक्षा जांच के लिए सभी संवेदी भाषण्डों को जांच-अवधि के अनुसार स्थापित किए जाने की जरूरत है । घरेलू उद्योग अपनी उचित बिक्री कीमत की वसूली करने में सक्षम नहीं रहा है और यह कि अगर समय पर कार्रवाई नहीं की गई गे इसे बंद करना पड़ सकता है ।

(ii) पांच प्रमुख उत्पादकों में से जोकि दिनांक 17.2.1998 को घरेलू उद्योग की ओर से दायर याचिका की पार्टी थे तीन उत्पादकों नामतः मै0 फैरो मैग्नेट्स एंड एलायड प्रोडक्ट्स लि�0, मै0 मैग्नेटिक्स इंडिया लि�0 और मै0परमानेट मैग्नेट्स लि�0 ने अपना प्रचालन बंद कर दिया है क्योंकि वे चीन से संबद्ध वस्तुओं के अनुचित रूप से पाटन के कारण गिरती हुई बिक्री कीमतों के दबाव को सहन नहीं कर सके ।

(iii) याचिकाकर्त्ताओं को सूचित किया गया है कि रोजगार क्षमता उन कारकों में से एक है जिसके कारण चीन की सरकार अपने यहां इस उद्योग को आर्थिक सहायता दे रही है । अगर पाटन-रोधी शुल्क लगाने से चीन से गिरती हुई बिक्री कीमतों में बदलाव नहीं आता है तो समूचा एचएफआरएम उद्योग बंद हो जाएगा ।

(iv) बेरियम कार्बोनेट पर नवंबर 1999 में पाटनरोधी शुल्क लगाने के कारण इसकी लागत में वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप तथा अन्य कारणों से एचएफआरएम की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है । मै0 डीजीपी हिनोडे इंडस्ट्रीज लि�0 ने 100 श्रमिकों को हटा दिया है और शेष श्रमिकों के प्रोत्साहनों में कमी कर दी है । एचएफआरएम उद्योग के औद्योगिक रोजगार, जोकि 1998 में 2500 था घटकर अब 700 रह गया है ।

(v) कुल कारोगार में आयातों का हिस्सा 1998-99 में 1462 मी0 टन था, जो बढ़कर 1999-2000 में 1767 मी0 टन हो गया है, दूसरी तरफ घरेलू उद्योग का हिस्सा 1998-99 के 5342 मी0टन से घटकर 1998-99 में 5242 मी0 टन और 1999-2000 में 5205 मी0 टन रह गया है । घरेलू बिक्री कीमतों में वृद्धि नहीं हुई है यद्यपि पाटन-रोधी शुल्क लगाने के बाद इसमें वृद्धि करने के विषय में सोचा गया था । वर्ष 1998 में प्रथम याचिका प्रस्तुत करते समय 50 रु प्रति किलोग्राम बिक्री कीमत की तुलना में इस वर्ष चालू बिक्री कीमत निम्नलिखित कारणों से घटकर 34 रु प्रति किलोग्राम रह गई है

(क) आयातकों ने सूचित किया है कि रिंग मेगनेट केवल तभी मेगनेट है अगर कोई स्पीकर या अन्य कोई उत्पाद बनाया जाता है और यह कि एचएफआरएम पर पाटन-रोधी शुल्क नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि ये मेगनेट बिल्कुल नहीं हैं।

(ख) हार्ड फेराइट रिंग मेगनेटों का आयात बीजक में लिखी गई अन्य वस्तुओं के साथ ही भारी मात्रा में किया जाता है ताकि संबद्ध वस्तुओं पर पाटन-रोधी शुल्क न लगाया जाए।

(ग) चीन में निर्मित मेगनेटों का आयात अन्य देशों के जरिए किया जाता है।

(vi) जो घरेलू संयंत्र बंद कर दिए गए हैं वे लाभ कमा रहे थे और केवल पाटन के कारण ही उन्हें क्षति होनी शुरू हुई। घरेलू याचिकाकर्ता कीमत में कटौती का सामना कर रहे हैं हालांकि वे क्षमता से अधिक लागत को झेल सकते हैं। अतः उन्हें पाटन से संरक्षण की जरूरत है। उपयोक्ताओं द्वारा उठाया गया क्षमता से अधिक और आंतरिक प्रतिस्पर्द्धा का मामला असंगत है और यह कि घरेलू उद्योग को उत्पादन पर बहुत हानियां हुई हैं।

प्रकटीकरण विवरण के उत्तर में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं

यद्यपि प्राधिकारी ने एक तरफ अपर्याप्त सूचना और निर्यातक के असहयोग को देखते हुए उत्पादन किए जा रहे और आयातित एचएफआरएम के विभिन्न आकारों और ग्रेडों पर ध्यान दिए बगैर सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन-मार्जिन के निर्धारण के लिए इस समीक्षा जांच के प्रयोजन से भारित औसत दृष्टिकोण को अपनाने का प्रस्ताव किया है लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने शुल्क के स्वरूप की सिफारिश करते समय विभिन्न ग्रेडों के मामले पर विचार करने का प्रस्ताव किया है। यह उल्लेख नहीं किया गया है कि इस पर किस आधार पर विचार किया गया है। हम प्राधिकारी से इसे स्पष्ट करने के लिए अनुरोध करते हैं।

रुपया *** पर एनआईपी का निर्धारण रुपया *** से काफी कम है, जैसा कि हमने अपनी याचिका में कहा था। हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि रुपया *** पर एनआईपी के निर्धारण के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के और ब्यौरे देखने

की अनुमति दी जाए । हम इस पर अपनी टिप्पणी देने के अधिकार को सुरक्षित रखते हैं ।

2. मै0 स्ट्रेटिजिक लॉ ग्रुप (जो मै0 सलोरा इंटरनेशनल, मै0 अहूजा रेडियो, मै0 करिस्मैटिक सांउड्स का प्रतिनिधित्व करते हैं) और मै0 मैगेनेट यूजर्स एसोसिएशन ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

- (i) अनेक घरेलू संयंत्र निर्यात के पूर्वानुमानों पर अनुरित थे । वास्तव में आज भी जब भारत में एचएफआरएम के केवल दो विनिर्माता हैं, तब भी समग्र क्षमता भारतीय संदर्भ में अधिक है ।
- (ii) तीन याचिकाकर्ताओं का उत्पादन किसी कथित पाटन के कारण बन्द नहीं हुआ है अपितु भारत के अन्दर उद्योग जगत में अत्यधिक आंतरिक प्रतिस्पर्द्ध के कारण हुआ है । मै0 मैगेनेटिक्स इंडिया लि�0 को एचएफआरएम के आयातों के शुरू होने से पहले 16 करोड़ रुपए की हानि हुई । यह इकाई एक "रूग्ण इकाई" थी जैसाकि 1996 में साईका के अंतर्गत परिभाषित किया गया है । एचएफआरएम-। के समय, मै0 फेररो मैगेनेट्स को पहले से ही हानियां हो रही थीं । ऐसा मुख्य रूप से संयंत्र के अव्यवहार्य अवसर के कारण हुआ । मै0 परमानेंट मैगेनेट्स के अनुचित रूप से ऊपरी खर्च अधिक थे और उनके पास अन्य जोखिम वाले काम भी थे जैसे रीयल एस्टेट परियोजनाएं और सहभागिता फर्म जो एचएफआरएम के विनिर्माण से सम्बद्ध नहीं थी । कम्पनी ने अस्तित्व रहित स्टॉकों के विरुद्ध ऋण लिए थे और ऋण देने वालों ने इसे बंद करने के लिए बाध्य कर दिया था । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एचएफआरएम के अन्य तीन उत्पादकों ने अपने कारोबार विभिन्न कारणों से बंद किए जो किसी भी कथित पाटन से सम्बन्धित नहीं थे ।
- (iii) एचएफआरएम के आयातों में कोई गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई नहीं दी और ऐसा दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं । विश्व के एचएफआरएम उद्योग के अनेक खिलाड़ी हैं जिनमें चीन तथा अन्य देश जैसे ताइवान, कोरिया, मलेशिया और इडोनेशिया आदि में बहुत से गैर-सरकारी प्रतिष्ठान शामिल हैं, जो विश्व भर में एक समान कीतों पर बिक्री करते हैं ।
- (iv) मै0 जीपी इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में एचएफआरएम के लिए मुख्य कच्चे माल के रूप में बेरियम कार्बोनेट की कीमतों में कमी आई है ।

(v) याचिकाकर्त्ताओं के इस दावे को कि उन्हें उद्योग में रोजगार कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा, वर्द्धित आटोमेशन के सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए। स्वयं याचिका में ही याचिकाकर्त्ताओं ने बताया है कि रोजगार में वृद्धि हुई है जिसकी संख्या 1998-99 को 420 से बढ़कर 1999-2000 में 426 हो गई है।

(vi) यदि याचिकाकर्त्ता 34/-रुपए प्रति किग्रा० की दर से अच्छी क्वालिटी के मैगेनेट की बिक्री कर रहे हैं थे तो आयातक 40/- रुपए से 45/-रुपए प्रति किग्रा० के बीच की पहुँच लागत पर मैगेनेट का आयात क्यों करेगे। अतः यह जरूरी है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस मामले की जांच पूरी तरह से तथा निर्णायक रूप से करे।

प्रकटन के उत्तर में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं

(क) यह उत्त्वेष्टनीय है कि घरेलू उद्योग ने इस तथ्य को उजागर किया है कि उन्हें चीन सहित विभिन्न देशों/स्रोतों से आयातों के कारण क्षति हो रही है। इससे पर्याप्त रूप में यह सिद्ध होता है कि घरेलू उद्योग का भी यह स्पष्ट मत है कि क्षति, यदि कोई है, तो वह अन्य देशों से आयातों के कारण हुई है। चीन की भूमिका गैर-मौजूदगी की है क्योंकि पाटनरोधी शुल्क पहले से ही लागू हैं। अतः घरेलू उद्योग की स्वीकार्यता के अनुसार भी कारणात्मक संबंध का अभाव है। चूंकि पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए आवश्यक घटकों की संतुष्टि नहीं होती है, इसलिए माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को केवल इस आधार पर ही समीक्षा कार्रवाई समाप्त कर देनी चाहिए।

उपर्युक्त अनुरोधों को नोट करने के बाद प्राधिकारी निम्नलिखित अभिमत व्यक्त करते हैं

(i) घरेलू उद्योग द्वारा सम्बद्ध वस्तुओं को उत्पादन 1998-99 में 5843.20 मी. टन था जो घट कर जांच की अवधि के दौरान (वार्षिक) 5108.8 मी० टन रह गया।

(ii) घरेलू उद्योग द्वारा सम्बद्ध वस्तुओं की बिक्री 1998-99 में 5843.20 मी० टन हुई थी जो घटकर जांच की अवधि में (वार्षिक) 5363.28 मी० टन रह गई।

- (iii) घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग 1998-99 में 50.85% था जो घटकर जांच की अवधि में 41.55% तक रह गया ।
- (iv) निवल बिक्री प्राप्ति 41.42 रुपए/किग्रा⁰ से कम हो कर 39.13 रुपए/किग्रा⁰ हो गई ।
- (v) जांच की अवधि में एनएसआर गैर-क्षति कर कीमत (एनआईपी) से कम रही जैसाकि जांच की समीक्षा अवधि में मूल्यांकित किया गया है जिससे घरेलू उद्योग को वित्तीय हानियां हुई है ।
- (vi) प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति के लिए मांग का कोई योगदान नहीं है और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पर पाटित आयातों के कारण हुई कीमत कटौती के मूल्यांकन पर किसी भी प्रकार की अकुशलता के प्रभाव को हटाने के लिए प्राधिकारी ने कच्चे माल, उपयोगिताओं आदि पर सर्वोत्तम उपयोगिता मनको की बैंच मार्किंग करके सम्बद्ध वस्तुओं की उत्पादन लागत को समुचित रूप से मानकीकृत किया है ।

उपर्युक्त कारक सामूहिक और संचयी रूप से यह दर्शाते हैं कि पाटित आयातों से भारतीय बाजार में कीमतों का कम होना जारी रहा जिससे निवल बिक्री आय में कमी आई और फलस्वरूप घरेलू उद्योग को वित्तीय हानियां हुई और यह कि पाटित आयातों के कारण कीमत कटौती से हुई क्षति से घरेलू उद्योग की रक्षा करने के उद्देश्य से पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता है ।

अन्य मुद्दे

निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- I. मै0 डीजीपी हिनोडे इंडस्ट्रीज लि�0 और मै0 जीपी इलैक्ट्रानिक्स लि�0
 - (i) निर्दिष्ट प्राधिकारी को गैर-क्षतिकर कीमत में वृद्धि करनी चाहिए, निश्चित आधार पर पाटनरोधी शुल्क डालर के रूप में निर्धारित करना चाहिए ।

(ii) पीए प्रणाली मे एचएफआरएम कुल लागत 2 % से भी कम है और पीए इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचाने के कारण के रूप मे उसे हटाया नहीं जा सकता ।

प्रकटन के उत्तर में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- i. पाटनरोधी शुल्क को लगाने का प्रयोजन निर्यातकों द्वारा किए जाने वाले पाटन के विरुद्ध घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करना है । इस मामले में घरेलू उद्योग को अलग-अलग तरीके से अर्थात् निश्चित आधार पर तथा परिवर्तनीय आधार पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के प्रभावों का अनुभव है । घरेलू उद्योग के अनुभव के आधार पर जब मूल रूप से पाटनरोधी शुल्क निश्चित आधार पर लगाया गया था तो आयात निमंत्रित हुए थे और घरेलू उद्योग की बिक्रियों मे वृद्धि हुई थी । तथापि जब अंतिम जांच निष्कर्षों के समय शुल्क परिवर्तनीय आधार पर लगाया गया तब आयातों में फिर वृद्धि हुई और शुल्क का प्रभाव निष्प्रभावी हो गया और घरेलू बाजार मे पांच कम्पनियों मे से तीन कम्पनियों को अपना कार्य बंद करना पड़ा । घरेलू उद्योग समझता है कि आयातक/व्यापारी वर्ग निर्यातकों के साथ गहरी साठ-गॉठ करके आयातों की कीमतों मे चालाकी कर रहा है । ऐसा जांच की अवधि के दौरान किए गए विभिन्न सौदों से स्पष्ट होता है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है । याचिकाकर्ता के इस तर्क कि परिवर्तनीय आधार पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क कोई प्रभाव नहीं पड़ा है इस तथ्य से भी पुष्टि होती है कि एचएफआरएम की मौजूदा बाजार कीमत 34 रुपए प्रति किग्रा 0 हैं जबकि पहुँच लागत की सीमा 34 रुपए प्रति किग्रा 0 निश्चित की गई है जैसाकि पूर्ववर्ती अंतिम निष्कर्षों में निर्धारित किया गया था ।
- ii. निर्धारित आधार पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से आयातकों के लिए अधिक बीजकांकन अथवा कम बीजकांकन से लाभ प्राप्त करने की कोई गुंजाइश ही नहीं क्वागी और इससे पाटनरोधी शुल्क लगाने का असली प्रयोजन सिद्ध होगा । हम अपने दावे को प्रमाणित करन के लिए इसके साथ दिनांक 20 सितम्बर 2000 के फाइनैसियल एक्सप्रेस मे

प्रकाशित एक प्रैस रिलीज संलग्न कर रहे हैं जहां डीआरआई ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रही वाणिज्यिक धोखाघड़ियों पर चिंता व्यक्त की है।

iii. हमने अपने अनेक पत्राचारों में प्राधिकारी से पहले ही अनुरोध किया है कि वे परिवर्तनीय आधार के बजाए निर्धारित आधार पर पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण करें क्योंकि इसी से उद्योग का और क्षति से बचाव हो सकता है क्योंकि परिवर्तनीय आधार पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से आयातित सम्बद्ध वस्तुओं के अनुचित पाटन विरुद्ध घरेलू उद्योग को समुचित संरक्षण प्रदान करने में असफलता मिली है।

2. मै0 स्ट्रैटिजिक लॉ ग्रुप जो सलोटा इंटरनेशनल, मै0 अहूजा रेडियो तथा मै0 करिस्मैटिक सांउंडस मैगनेट्यूजर्स एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

- i) यह स्वीकार किया गया है कि डीसीसीआई एंड एस द्वारा संकलित किए गए आंकड़े एचएफआरएम के आयातकों के लिए उचित नहीं हैं। गैर-सरकारी स्रोत जहां से याचिकाकर्ताओं ने आंकड़े एकत्र किए हैं, उन्हे गोपनीय रखा गया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी की सगत परिपाटी के अनुसार तथा इक्विटी की खातिर, हितबद्ध पक्षों के बीच कार्रवाईयां हमेशा विपरीत ढंग से होती है जिसमें विरोधी पक्ष द्वारा प्रदान की गई सूचना की जांच करने तथा उस पर टिप्पणियां करने का अवसर मिलता है। सूचना के स्रोत को सुरक्षित रखने से उपभोक्ता उद्योग को मूल सिद्धांत से वंचित किया जा रहा है।
- ii) एचएफआरएम की अनेक किस्मों के हाते हुए यह उत्पाद निश्चित शुल्क लगाने के लिए उपयुक्त नहीं है और यह कि यह एक निर्धारित सिद्धांत है कि संदर्भ मूल्य एक अच्छी पद्धति है जब आयातों का मूल्य कम आंका जाता है अथवा जब असली खतरा सरत्तेश्यातों से होता है।

(iii) अधिकांश इलैक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए मानक निविष्टि-उत्पादन मानदण्ड उपलब्ध नहीं हैं और उपभोक्ता उद्योग डीईपीबी पर निर्भर है, जिसके संबंध में निर्यातों के लिए पाटनरोधी शुल्क की माफी उपलब्ध नहीं है ।

(iv) आयातों की उपलब्धता से पहले इन्हीं याचिकाकर्ताओं ने उत्पादक संघ की कीमतों का सहारा लिया था जैसा कि एचएफआरएम-1 में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है ।

(v) भारतीय घरेलू उत्पादक वैश्विक स्तर पर समान कीमत पर एचएफआरएम की बिक्री करते हैं जिसे सार्वजनिक सुनवाई के समय स्वीकार किया गया था । इसलिए, भारतीय घरेलू उपभोक्ताओं को याचिकाकर्ताओं द्वारा एचएफआरएम के निर्यातों पर आर्थिक मदद देने के लिए उच्च कीमतों के भुगतान हेतु बाध्य नहीं किया जाना चाहिए । उच्च एचएफआरएम कीमतें पी ए प्रणालियों और एम्प्लीफायर प्रणालियों के भारतीय निर्यात को संकट में डाल देंगी जिसके लिए अग्रिम लाइसेंस संबंधी लाभ के अभाव में प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर एचएफआरएम की जरूरत होगी ।

प्रकटन विवरण के उत्तर में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

(क) आयातकों को इस बात पर जोर देना चाहिए कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्यातों पर प्रभाव के बिना पाटनरोधी शुल्क की अपेक्षा नहीं कर सकते । माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी उसी मंत्रालय के एक अंग हैं और जिनका एक काम निर्यातों को निर्धारित करना है, अन्यथा भारत सरकार और मंत्रालय का निर्यात संवर्धन वातावरण समाप्त हो रहा है । यह नोट किया जाए कि पीए प्रणालियों में याचिकाकर्ताओं द्वारा इंगित 2 % की एचएफआरएम की लागत पूर्णतः कल्पनातीत है तथा गलत है और यह 15 % से 20 % तक अधिक हो सकती है ।

(ख) विनम्र एवं तात्कालिक अनुरोध है कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी स्थिर निर्यात उद्योग पर बढ़े हुए शुल्कों के प्रभाव को ध्यान में रखें ।

(ग) प्रकटन विवरण से यह संकेत मिलता है कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने ' बिभिन्न ग्रेडों, संदर्भित मूल्य की पर्याप्तता और इस बात पर ध्यान देने का प्रस्ताव किया है ' कि क्या घरेलू उद्योग

को शुल्क की सिफारिश करने के लिए ऐसे मामलों में अपेक्षित संरक्षण एवं संगत व्यवहार मिला हुआ है।

इस संदर्भ में हमारा सविनय निवेदन है कि चूंकि यह केवल समीक्षा याचिका है इसलिए शुल्क के प्रकार या स्वरूप को बदलना उचित नहीं होगा। ऐसा करना पाटन मार्जिन के बारे में इस मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुरूप भी होगा। इसलिए हमारा अनुरोध है कि अकेले उपरोक्त अनुरोध को ध्यान में रखते हुए रूपए के रूप में संदर्भ मूल्य भी जारी रहना चाहिए। इसके अलावा, इस मामले में संदर्भ मूल्य भी पूर्णतः न्यायोचित है जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी ने भार के आधार पर विभिन्न आकारों और ग्रेडों को सामान्य वर्ग में लाने का प्रस्ताव किया है। स्पष्टतया, निर्दिष्ट प्राधिकारी का उद्देश्य अत्यधिक भिन्न-भिन्न कीमतों पर आ रहे सामान पर पाटनरोधी शुल्क की समान राशि को लगाना नहीं हो सकता है। एक निश्चित शुल्क के तरीके में परिवर्तन करने का केवल यह अर्थ होगा कि कम कीमत के साथ-साथ उच्च कीमत की मैग्नेट पर शुल्क की समान राशि वसूल की जाएगी जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध होगा।

(घ) विनिमय की प्रचलित डालर दर पर शुल्कों को लगाने के संदर्भ में यह अनुरोध किया जाता है कि माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी इस समीक्षा याचिका में इस कार्ययाही से बचें, विशेष तौर पर इस तथ्य को देखते हुए कि रूपए के मूल्य में हाल ही में आई गिरावट के कारण आयात लागत पहले से ही अस्थिर चल रही है और इस तथ्य के मद्देनजर कि डीईपीबी योजना के तहत पाटनरोधी शुल्कों की प्रतिपूर्ति नहीं होती है।

ड. पहुंच मूल्य

इस उद्देश्य के लिए आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमाशुल्क द्वारा यथा आकलित निर्धारणीय मूल्य होगा और उसमें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 एवं 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर, सभी सीमाशुल्क शामिल होंगे।

(घ) भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि समीक्षा की शुरुआत पाटन में वृद्धि होने और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बारे में घरेलू उद्योग के अभ्यावेदन पर की गयी है।

उपयोगकर्ता उद्योग ने पी.ए. प्रणाली, जिसमें संबद्ध वस्तु का उपयोग होता है की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर पाटनरोधी शुल्कों के प्रभाव का संकेत दिया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपयोगकर्ता उद्योग ने एग्जिम नीति की डीईपीबी प्रणाली के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्कों को वापस नहीं किए जाने का संकेत दिया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपयोगकर्ता उद्योग के डीईपीबी प्रोत्साहन संबंधी अनुरोधों पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा एग्जिम नीति की सीमा के अंतर्गत समुचित रूप से विचार किए जाने की जरूरत है। प्राधिकारी मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तु के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं और इस प्रकार इन संबद्ध वस्तुओं के उपयोग से विनिर्दित उत्पादों पर भी प्रभाव पड़ सकता है, तथापि, पाटनरोधी शुल्कों के जारी रहने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी क्योंकि पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य पाटन के अनुचित व्यापार व्यवहार के जरिए निर्यातकों द्वारा प्राप्त लाभ के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करना है। भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल करने से घरेलू उद्योग का हास रुकेगा तथा उपयोगकर्ताओं और उपभोक्ताओं को संबद्ध वस्तुओं के व्यापक विकल्प उपलब्ध रहेंगे। पाटनरोधी शुल्कों के जारी रहने से संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात किसी भी प्रकार प्रतिबंधित नहीं होंगे।

प्राधिकारी मूलता के देश के बारे में गलत घोषणा करके पाटनरोधी शुल्कों के अपवंचन, अनमैग्नेटाइज्ड एचएफआरएम को मैग्नेट न कहकर संबद्ध वस्तुओं की निकासी और आमेलन का सहारा लेकर अधिक बीजक तैयार करने की घटना से संबंधित अनुरोधों को नोट करते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन तथ्यों को देखते हुए घरेलू उद्योग ने परिवर्तनीय शुल्क के बजाए निश्चित शुल्क लगाने का अनुरोध किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनमैग्नेटाइज्ड रूप में भी एचएफआरएम संबद्ध वस्तु की श्रेणी में आएगा क्योंकि अनमैग्नेटाइज्ड रूप में संबद्ध वस्तु की आपूर्ति करना एक तकनीकी जरूरत है और इसलिए जैसा कि पैरा ख (क) (3) में भी स्पष्ट किया गया है अनमैग्नेटाइज्ड एचएफआरएम भी विद्याराधीन संबद्ध वस्तु है। जहां तक मूलता के देश की गलत घोषणा करने का संबंध है, इस प्रक्रिया पर सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा आयात के समय सावधानीपूर्वक जांच करने की जरूरत है और जैसा कि उम्पर उल्लेख किया गया है कि परिवर्तनीय शुल्क द्वारा अपवंचन की दोनों प्रकार की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। जहां तक पाटनरोधी शुल्कों से बचने के लिए संबद्ध वस्तुओं के आमेलन और परिणामस्वरूप संबद्ध वस्तुओं के अधिक बीजक तैयार करने का संबंध है, प्राधिकारी ने उपरोक्त पैरा ग में यह संकेत दिया है कि

याचिकाकर्ता द्वारा संबद्ध वस्तुओं की कुछेक खेपों के बारे में दिया गया यह तर्क कि उनके आयात संभवतः काफी अधिक कीमतों पर हो रहे हैं, जांच के बाद सही नहीं पाया गया था । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता की जांच अवधि के दौरान निबल बिक्री प्राप्ति (दोनों घरेलू उत्पादकों) संदर्भ कीमत स्तर से काफी अधिक है जिससे यह पता चलता है कि प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित संदर्भ स्तर पूर्व में निर्धारित स्तर से निबल बिक्री प्राप्ति को अधिक रखने में काफी सक्षम है । इस तथ्य को भी देखते हुए कि इन ग्रेडों की किस्मों की कीमतें अलग-अलग हैं और यह कि पाटन मार्जिन के लिए भारित औसत दृष्टिकोण को अपनाया गया है, यह उचित होगा कि परिवर्तनीय शुल्क के द्वारा पाटनरोधी शुल्कों की वसूली की जाए जैसा कि पूर्ववर्ती जांचों में किया गया है ।

छ. निष्कर्ष

उपरोक्त पर विचार करने के पश्चात यह पाया गया है कि:

- (क) संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं का भारत को उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है ।
- (ख) संबद्ध देश से पाटित संबद्ध वस्तुओं की कम पहुंच कीमतों के कारण कीमत में आई गिरावट की वजह से कम निबल बिक्री प्राप्ति होने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को वार्तविक क्षति हुई है जिससे वित्तीय घाटा हुआ है ।
- (ग) संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन के द्वारा घरेलू उद्योग को क्षति हुई है । प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित अध्याय 85 के अंतर्गत आने वाली संबद्ध वस्तुओं के सभी स्वरूपों/ग्रेडों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं । पैरा ख (क) (3) में यथा उल्लिखित आकार के किसी ग्रेड के एचएफआरएम पर भी पाटनरोधी शुल्क लागू होंगे ।
- (घ) यह भी महसूस किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क को वापस लेने/जारी रखने से पाटन में आगे और वृद्धि होगी और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होगी ।
- (ङ.) पाटन मार्जिन के बराबर या उससे कम पाटनरोधी राशि की सिफारिश करने पर चिचार किया गया था ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त किया जा सके । तदनुसार, यह प्रस्ताव है कि सीमा शुल्क टैरिफ के अध्याय 85 के सीमाशुल्क उपशीर्ष संख्या 8505.19 के अंतर्गत आने

वाले चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबंध वस्तुओं के सभी ग्रेडों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा पहुंच मूल्य और नीचे कालम 3 में दर्शायी गई राशि के बीच के अंतर की राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए ।

क्रम सं०	निर्यातक/उत्पादक का नाम	उत्पाद	राशि अमरीकी डालर/मी० टन
1	2	3	4
1.	<u>चीन जनवादी गणराज्य</u> सभी निर्यातक/उत्पादक	पैरा ख (क) (3) में यथाउलिलखत एचएफआरएमके सभी ग्रेड और साईज	1123.8

इस आदेश के खिलाफ कोई अपील उक्त अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, स्वर्ण (नियंत्रण) न्यायाधिकरण के समय दायर की जा सकेगी ।

एल.वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 23rd October, 2001

Sub:— Review of Anti-Dumping Duties Concerning Imports of Hard Ferrite Ring Magnets (HFRM) from PR China—Final Findings

No. 65/1/2000-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof:

A. PROCEDURE

1. The Procedure described below has been followed:

i) The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), under the Rules, received from M/s DGP Hinoday Industries Ltd., Pune and M/s G.P. Electronics Limited, Nashik, (also referred to as petitioner in this notification), a request for

review of Anti-Dumping duty imposed on imports of Hard Ferrite Ring Magnets (HFRM) (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from PR China (hereinafter referred to as subject country).

- ii) The Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the petitioner, decided to initiate review investigations against imports of HFRM from PR China. The Authority issued a public notice dated 23.12.2000 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating review investigations concerning imports of HFRM originating in or exported from PR China.
- iii) The investigations concluded by the Authority vide notification dated 12.7.1999 have been referred to as "the previous investigations" in this notification.
- iv) Request was made to the Central Board of Excise and Customs (CBEC) to furnish details of imports of HFRM in India during the period of investigation considered in the review investigation
- v) The Authority notified the Embassy of the subject country in New Delhi before proceeding to initiate the review investigation in accordance with sub-Rule 5(5) of the Rule.
- vi) The Authority held a public hearing on 2.7.2001. The parties attending the oral public hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and were requested to offer their rebuttals./rejoinder.
- vii) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained and kept open for inspection by any interested party.
- viii) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to all known interested parties on 16.9.2001 and comments received on

the same have also been duly considered in these findings to the extent they are relevant and have bearing on the case.

- ix) The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known importers (whose details were made available by petitioner and were available earlier during the previous investigation) of HFRM in India and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of issue of the letter.
- x) The Authority provided a copy of the petition to the known exporters and the Embassy of the subject country in accordance with Rules 6(3) supra. A copy of the petition was also provided to other interested parties, wherever requested.
- xi) The Authority sent a questionnaire to elicit relevant information to the following known exporters/producers from the subject country in accordance with the Rule 6(4):
 1. M/s China Ningbo International Cooperation Group Company Ltd., China
 2. M/s Zhejian Dongyang Magnetic Enterprise Group Company Industry Zone,
 3. M/s China National Electronics Import & Export Shanghai Company, China
 4. M/s China National Electronics Import & Export SHENZHEN Company
 5. M/s China Greatwall, China
 6. M/s O.K. Gidumal & Watumullt., Hong Kong
 7. M/s Dongyong Magnetic Enterprise Group Corporation, China
 8. Mr Jawahar, 37-41, Shan Mei Street, Flotan Shatin, Hong Kong

The response to the questionnaire/notification was filed by none of the exporters/producers

However, China Chamber of Commerce for import and export of machinery and electronics product have responded to the Disclosure Statement dated 14.9.2001 and cost of production provided by M/s China National Imports and Exports Ziejiang company.

xii) The Embassy of the subject country in New Delhi were informed about the initiation of the review investigation in accordance with Rule 6(2) with a request to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter, petition and questionnaire sent to the exporters was also sent to the Embassy, alongwith a list of known exporters/producers.

xiii) A questionnaire was sent to the following known importers/user associations of the subject goods for necessary information in accordance with Rule 6(4):

1. Mr Naresh Uppal, Delhi
2. M/s Prince Electronics, Delhi
3. M/s G.M. Overseas, New Delhi
4. M/s S.K. Trading, Delhi
5. M/s Rama Krishna Sales Corporation, Delhi
6. M/s JRC Industries, Mumbai
7. M/s Ankit Electronics, Delhi
8. M/s Goodwill Electronics
9. M/s Gaurav Electronics, Delhi
10. M/s Rollet Industries, Delhi
11. M/s S. Mehta & Company, Mumbai
12. M/s Kalwar Exports, Mumbai
13. M/s Salora International, New Delhi
14. M/s Ahuja Radio, New Delhi
15. M/s Karismatic Sounds, New Delhi
16. M/s Magnet User's Association, New Delhi

Response to the questionnaire/notification was filed by the following Importers/user Associations:

1. M/s Salora International(through Strategic Law Group)
2. M/s Ahuja Radio (through Strategic Law Group)
3. M/s Karismatic Sounds(through Strategic Law Group)
4. M/s Magnet User's Association
5. M/s JRC Industries, Mumbai

xiv) Information regarding injury and imports of the subject goods was sought from the domestic producers Viz M/s_DGP Hinoday Industries Ltd. And M/s G.P Electronics Limited

xv) Cost investigation was also conducted for domestic industry so as to work out optimum cost of production and cost to make and sell HFRM series in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).

xvi) ****in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules;

xvii) Review investigation was carried out for the period 1.4.1999 to 30.6.2000 i.e. the period of investigation (POI) for the review.

B. VIEWS OF PETITIONERS, EXPORTERS, IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES AND EXAMINATION BY AUTHORITY

The views expressed by the various interested parties have been stated in the disclosure statement. The views raised in response to the disclosure statement are discussed in the relevant paras herein below to the extent these are relevant as per rules and have a bearing upon the case. The arguments raised by the

interested parties have been examined, considered and, wherever appropriate, dealt in the relevant paras herein below.

A) Product under consideration and Like Article

1. M/s DGP Hinoday Industries Ltd., Pune and M/s G.P. Electronics Limited, Nashik have made the following submissions:-

- (i) The production under consideration is Hard Ferrite Ring Magnets, which finds its application in loudspeakers/ PA System/Telecommunications and various other applications.
- (ii) Strontium grade HFRM is more expensive and used for higher applications and its usage in the Indian market is less than 1%. Within the barium grades, the cost difference to an extent of 30% to 40% as indicated by the importers is ridiculous. We have excluded Hard Ferrite products like magnets and motor magnets.
- (iii) The constructed cost given by the domestic industry is of Barium Ring magnets and the strontium magnet cost is categorically excluded.

2. M/s Strategic Law Group representing (M/s Salora International, M/s Ahuja Radio and M/s Karismatic Sounds) and the Magnet User's Association have made the following submissions:

- (i) HFRM have several uses and are of different qualities. They range from Y8 to Y35 grade and have widely different costing. The Petitioners seek imposition of anti-dumping duties on both Barium and Strontium for which the costs are fundamentally different. In addition to these, hard ferrite magnets came in shapes other than rings also, which do not fall within the scope of the investigation. Difference between the cost between Y8 and Y35 is as high

as 35-45%. Normally, HFRM produced by strontium ferrite is more expensive than that produced by barium ferrite by about 20-25%.

- (ii) In fact, in HFRM-1(original investigation), the Hon'ble Designated authority specifically did not include Strontium HFRM. Thus, it is not open now to widen the scope of the product under consideration in this review Petition.
- (iii) A review by definition is more limited than a new investigation and must be restricted to only those parameters, which have changed from the initial period. In original investigation(HFRM-1) the DA had accepted that Chinese producers have 25% cost advantage, which the petitioners had themselves conceded. The methodology adopted by DA was not challenged by the domestic industry before the Hon'ble CEGAT and therefore DA at this stage can only examine the change in numbers and would be logically restricted in changing the basis

In response to the Disclosure, M/s Strategic Law Group(SLG) has made the following submissions.

- (a) It is important to note that the petitioners have themselves in their application have given the technical specifications corresponding to the Y-25 grade. This would unambiguously imply that the scope for the product under consideration for review purposes is restricted to the Y-25. The review, therefore, should be restricted only to the Y-25 grade and cannot be extended to any other grade.
- (b) The Petitioners sought to include Strontium grade HFRM in the review. However, it seems that now

they are withdrawing the case for alleged dumping against Strontium grade HFRM.

- (c) The statement by domestic industry regarding the price difference between the various grades of magnets is ridiculous. It may be observed that the price difference in the various barium grades is to the extent of 30 to 40% has been backed up with data of Y -25 magnets imported by M/s Salora and Ahuja Radios. Import data of Y-20 grade imported by M/s Karishmatic Sounds was also provided showing a price difference 15 to 20% between the Y-25 and the Y-20 Grade. It is apparent that the Y-8 and Y-15 grades would be significantly cheaper than the Y-25 grade and Y-30, Y -35 grades would be significantly more expensive than the Y-25 grade. Thus, the difference between the Y-35 and Y-8 grades would be approximately 40%.
- (d) The assertion by the Petitioners that Strontium grade magnets comprised of less than 1% of the Indian market is completely misleading, rather its usage contributes 15% to 20% of the market If the Hon'ble Designated Authority has taken into consideration only 1% for the purpose of calculation of NIP, it would give a totally wrong and highly inflated NIP. We would request the Designated Authority to kindly ensure that the attempt by the domestic industry to increase its cost for the purpose of calculation of NIP does not succeed. We request to let us have the non-confidential version of the disclosure statement dealing with NIP calculations so as to offer our comments on the same.

(e) The Consuming industry while noting that the product under consideration remains unchanged in the Review wishes to point out that the magnets other than Ring magnets of only Y-25 grade should be excluded from the purview of the Anti dumping duty.

(f) With reference to reduction of all sizes to a common denominator for comparison purposes, the consuming industry requests that the Hon'ble Designated Authority consider that the cost differential based on grades is not amenable to this, and each grade should be treated differently. Notwithstanding the fact that there is no co-operation from the exporters, the data produced by the importers should suffice in this analysis. The exporters from China have submitted to Hon'ble Designated Authority the production cost data of Y-25 grade magnets which should also be taken into account as a part of the best information available, and data should be considered for construction of cost from China and can be got verified if required.

3. EXAMINATION BY AUTHORITY

The Authority notes the submissions made by various interested parties and keeping in view the fact that the present investigation is only a review considers it appropriate to confirm the scope of investigation with respect to product under consideration as given in Para C(3) of Final Findings dated 12.7.99. The product under consideration is Hard Ferrite Ring Magnets used in manufacture of loud speakers, public address systems, magnetic assemblies etc.. The product is made from Barium Carbonate and Strontium Carbonate also. The Ring magnets are of varying sizes in terms of outer diameter ranging from 22 mm to 280 mm and inner diameter from 12 mm and 180

mm and having thickness 12 mm to 180 mm depending upon required use. HFRM is classified under Customs head 8505 of Schedule 1 of Customs Tariff Act, 1975. The subject goods imported in unmagnetised form also are covered in the scope of investigation.

B) DOMESTIC INDUSTRY

The Authority notes that there are no submissions made by any of the interested parties on the standing of the petitioner. The Authority further notes that out of the the five domestic producers who filed the previous petition, three of the units are closed and at present there are only two producers viz. M/s DGP Hinoday Industries Ltd, Pune and M/s G.P. Electronics Limited, Nasik of HFRM in the country who constitute the domestic industry within the meaning of the Rule 2(b)

C. DUMPING, NORMAL VALUE AND EXPORT PRICE

The Authority notes that the following submissions were made by different interested parties in response to the initiation of the investigation:

1. M/s DGP Hinoday Industries Ltd., Pune and M/s G.P. Electronics Limited, Nashik have made the following submissions:

(i) We had earlier agreed to the cost benefits to the Chinese producers on account of automation, cheap labour, cheap power, higher productivity and economies of scales as compared to the scale in India. As China has been presumed to a non-market economy, normal value is not required to be determined on the basis of domestic prices in China. As such the benefits given earlier while calculating the normal

value based on the domestic prices in China is no longer relevant in this case. Since exporters from China have decided not to cooperate, information given by the petitioner becomes the best available information. We also submit that in the CEGAT Judgment it is only the exporters who can challenge the normal value and the importers have no right to challenge the same.

- (ii) We have worked out export price from import transactions taken from import data collected from the private agencies as evidence of export price. The same could not be collected from DGCIS, since their data classified under Chapter 8505.19 has variety of magnets. We have worked out the export price as ** Rs/kg. We request DA to ask the interested parties to submit their complete details of imports giving quantities in a number of pieces as well as the corresponding net weight of imports. The information given by the petitioners may be relied upon rather than the importers who have resorted to practice of bunching and thereby evading anti-dumping duties.
- (iii) The cost advantage on factors such as automation, cheap labour and power, high productivity and economies of scale were granted without taking into account the different kind of subsidies. As per anti-dumping rule 44/99-CUS N.T.) dated 15.7.99 and 27/2001 - CUS N.T. - 31/5/2001, the cost advantage given to China are no longer relevant. India was considered as Surrogate country in the past. As Chinese exporters have not cooperated, the provisions of Annexure I Para 7 and 8 of the anti-dumping rules be applied to determine the normal value.

(iv) The adjustments of ocean freight, commission, insurance, inland transportation and port expenses, be considered for evaluating ex-factory export price.

In response to the disclosure, following submissions have been made:

(i) Unlike the earlier findings, the Authority has proposed to construct Normal value on the basis of international raw material prices completely ignoring the present law with respect to constructing of Normal value for Non Market Economies like China.

(ii) On the one hand the Authority says that, "as this a review investigation it proposes to adopt methodology and consider adjustments on cost advantage as done in the earlier findings", and on the other hand it has changed the methodology for constructing Normal value by taking international prices of raw materials which is clearly contradictory.

(iii) It is a well-settled law that though Exporter has a right to question the determination of Normal value, the importers/ users do not have such right. The authority though on the one hand says that the exporter has not cooperated in the Investigation but on the other hand has accepted the argument given by the importers/user that the cost advantage of 25% as given in the earlier findings should be retained. This approach of the Authority is in clear contradiction to the law on this matter.(

CEGAT judgement reference no AIIGMA Vs. DA 2000 (119)(E.L.T)333.

(iv) The Authority has stated that the review investigation has been carried out as per Rule 23 of the Anti Dumping Rules. Rule 23 *inter alia* states as under:

"The provisions of rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 shall be mutatis mutandis applicable in the case of review."

Annexure 1 to Anti Dumping Rules has been amended vide Notifications dated 15.7.99 and 31.5.2001 (as accepted by the authority in the disclosure statement). The Authority while constructing the Normal value has completely ignored the fact that for Non Market Economies like China the methodology for constructing Normal value is clearly given in Paragraph 7 & 8 to Annexure 1 of the Anti Dumping Rules (Details given below in para 5) as it stands today and thus its proposal to continue with the cost advantage of 25% is in clear contradiction of Rule 23, which states that the provisions shall mutatis mutandis be applicable and thus the Normal value has to be constructed as per the present law on this subject.

In this connection we would also like to refer to the provisions of Rule 10 which relates to the determination of Normal value, Export Price and Margin of Dumping. In accordance with the Provisions of Rule 23, the Normal value has to be reworked under Rule 10 and the same should be

determined considering the law prevailing at the time of final findings and the other factors related to it.

(v) China is presumed to be a Non Market Economy and the Normal value has to be calculated as per amended Paragraph 7 and 8 to Annexure 1 of the Anti Dumping Rules. As per Paragraph 7, Normal value should be determined as under :-

- a. on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or
- b. Where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin.

As per Paragraph 8 to Annexure 1 of the Anti Dumping Rules, unless it is shown on the basis of sufficient evidence in writing by the exporter in China that market conditions prevail in their economy, no other method for constructing the Normal value can be followed except that which is mentioned above in Paragraph 7 to Annexure 1 of the Anti Dumping Rules. As such we have strong reservations to the mode of constructing Normal value on the basis of international prices of raw materials which would only be an estimate. When the law permits for the construction of Normal value on the basis of price actually paid or payable in India then why should the Normal price be constructed on an estimated basis.

Moreover constructing Normal value on the basis of international prices of raw materials does not satisfy the condition of weighted average Normal value as have been contemplated in law and proposed by the Authority. The weighted average Normal value is determined taking into account the cost of production during the entire period of investigation which when divided with the actual production gives the weighted average cost of production and thus the weighted average Normal value.

(vi) In the disclosure statement it is also mentioned that the Authority proposes to adopt the methodology and consider adjustments on cost advantage (i.e. 25%) as done in the earlier finding. Since exporters in China have chosen not to participate in the investigation process and are presumed to be a Non Market Economy and thus cost advantage of 25% given in the earlier findings cannot be considered this time for the following reasons:

1. The Normal value can only be constructed as per Paragraph 7 to Annexure 1 of Anti Dumping rules as per the amendments to the Anti Dumping Rules made vide anti dumping rule 44/99 - CUS N.T dated 15.7.99 and 27/2001- CUS N.T dated 31.5.2001.
2. The investigation period has changed and thus Normal value should be constructed in accordance with Paragraph 7 & 8 to Annexure 1 of the Anti Dumping Rules taking into account the actual cost of production during the changed investigation period rather than on the estimated basis.
3. In a Non Market Economy like China, the various parameters of production leading to lower cost of production are the results of different kind of

government subsidies and not because of any productivity factors as was mentioned earlier.

We therefore urge the Authority to make necessary alterations in its proposal, as the method proposed to be followed is neither in accordance with the provisions of Rule 23 nor in consonance with the spirit of Anti Dumping Investigation which needs to be based on actual facts to be considered on the basis of best available information as against the mere estimates.

EXPORT PRICE

The Authority has proposed to construct weighted average of all such import transactions whose details are available from all the sources. We would like to invite the attention of the Authority to our letter dated 23rd July, 01 wherein we have given the details of some of the import transactions during the period of Investigation.

The perusal of these transaction reveals that how the same product can be imported from the same country at the same time at a substantially different prices. Such transactions cannot be considered to have been made in the ordinary course of international trade. We request the Authority to verify the supporting documents and evidences produced by these parties to ensure their genuineness before considering them for working out the weighted average export price or else otherwise they should be completely disregarded.

2. M/s Strategic Law Group (representing M/s Salora International, M/s Ahuja Radio and M/s Karismatic Sounds) and Magnet Users Association have made the following submissions:

- (i) The Petitioners have constructed a single normal value and are claiming a baseless and unreliable low export price to seek the imposition of one flat anti-dumping duty.
- (ii) Clubbing of different types and qualities of magnets meant for a wide range of applications is not in accordance with the practices and the jurisprudence on the subject. The requirement of 'Fair Comparison' demands that comparison need to be made on an apple-to-apple basis, and all factors, which affect price comparability, should be taken into account. It would therefore be legal and logically appropriate if at least the cost of production and the different prices of raw materials are duly reflected while calculating the dumping margin as well as the injury margin. We, therefore, request that the range of products in terms of size, quality and grades must necessarily be taken into account while calculating the cost of production for the domestic industry
- (iii) Cost of the production of subject goods in PR China have been provided by the importers.
- (iv) The import data supplied by the petitioners is incorrect and prejudicial, which is either by way of duplicate entries or is outside the POI.
- (v) Magnet User's Association have collected import data of about 724.6 Mt, which the DA can audit.

In response to the Disclosure following submissions have been made:

- (a) The Consuming Industry notes that the principles of 'non-market economy' as envisaged in the notification dated 31.5.2001 would not be applicable, as the case was initiated before the amendment in the Rules. We submit that the Designated Authority may therefore, kindly avoid any reference to the said notification.
- (b) Furthermore, we understand that the methodology of costing would remain unchanged adopting the same principles as were done in HFRM-I, including the admitted cost advantages. We also understand that only the internationally prevailing raw material prices and costs would be applied. It is requested that the Hon'ble Designated Authority may make no "appropriate adjustments" that would differ from HFRM-I if they are to the prejudice of the consuming industry, unless disclosed to the importers.
- (c) It is also noted that the Hon'ble Designated Authority will rely on data produced by the importers and the Department of Revenue (Customs Authorities). It is understood that the data of the Customs Authorities is reproduced by DGCI&S.
- (d) It is requested that in the event that this data is differently, the same needs to be disclosed to the importers.

EXAMINATION BY AUTHORITY

NORMAL VALUE

Under Section 9A(1)(c), normal value in relation to an article means:

- (i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
- (ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:-
 - (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub section (6); or
 - (b) the cost of production of the same article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

The Authority notes the submissions made by various interested parties as above. The Authority also notes that none of the

exporters has cooperated through a proper structured questionnaire response though cost of production of Y 25 grade of HFRM was provided by China National Electronics Import and Export, Zhejiang Company for the year 1999-2000 and not exactly for the POI. This information is also not as per the format of response sought for and is not complete. The Authority has, therefore, under such circumstances constructed the normal value as per Rule 6(8) on the basis of the best available information. The Authority also notes that the petitioner has submitted that in view of the amendment notified vide Customs Notification dated 31.5.2001 on provisions of non-market economy in respect of certain countries including China, the normal value should be considered on the basis of price of subject goods paid/payable in India without granting any cost advantage to the exporter as these advantages are on account of subsidies prevailing in China and that international raw material prices also need not be referenced as it is only the price payable in India which is relevant as per the amended rules. Further, it has also been indicated by the petitioner that such an approach is justified since none of the exporters from China have cooperated.

M/s Strategic Law Group representing importers viz. M/s M/s Salora International, M/s Ahuja Radio and M/s Karismatic Sounds) has mentioned that Customs Notification dated 31.5.2001 cannot be applied retrospectively. The Authority after examining these submissions notes that since there has been no structured response to the questionnaire from any of the exporters/producers from PR China, the normal value of subject goods in the subject country would need to be constructed on the basis of best available information. The Authority also notes that though the initiation of the anti dumping investigation was done prior to amendment in anti dumping rules, the Authority is well within the provisions of the rules to adopt a reasonable basis to construct

the normal value even as provided under the amended rules. Therefore, the Authority has adopted a reasonable basis which would include appropriate adjustments on cost advantage as earlier claimed by the petitioner and raw material at international prices to construct the normal value. The Authority notes that the present investigation being the review, the methodology on adjustments on cost of production to an extent of 25% granted to exporters in PR China in the earlier investigation are also appropriate for admission now since the petitioners have not to the contrary brought out any reasonable basis/evidence for withdrawal of the same. The Authority has, therefore, constructed the normal value by considering cost of production of the subject goods provided by the domestic industry and as verified by the investigation in the POI with raw materials considered at the international prices and 25% cost advantage on costs other than raw material. The weighted average normal value of the subject goods in the subject countries in the POI comes to xxx Rs. per kg.

EXPORT PRICE

The Authority notes the submissions made by the petitioner, M/s Strategic Law Group (SLG) and M/s Magnetic User's Association on adopting the sources of import data for the subject goods. The Authority has verified the data provided by M/s Salora International, M/s Ahuja Radio and M/s Karismatic Sounds. It was indicated by the petitioners that M/s Karismatic Sounds have imported two consignments of subject goods dated 9.2.2000 and 8.3.2000 at exorbitant prices. These details were requested by the petitioner to be verified before adopting data provided by the importers. The Authority has verified documents pertaining to these import consignments and noted that imports have been made at prices which are comparable to the other normal export transactions. Therefore, the submissions of the petitioners are

not found to be tenable. The Authority has, therefore, discarded in respect of these imports, the data provided by the petitioner from the secondary sources and has adopted the import data as verified by the Authority in respect of M/s Salora International, M/s Ahuja Radio and M/s Karismatic Sounds . The Authority also notes that the petitioner has from three secondary sources viz. World Trade Centre, Mumbai Bureau of Commercial Intelligence and Statistics and Impex Statistical Services, Mumbai, provided import prices of subject goods to an extent 724 Mts. The Authority has also received the import data from Customs and also from M/s JRC Industries, Mumbai. The Authority has adopted the relevant data of Customs and M/s JRC Industries for evaluating the import price. The Authority also notes that the petitioner has provided the import data in respect of relevant sizes and subject goods where the weight of subject goods was available to an extent of 225 MT. All relevant import data from different sources as indicated above has been adopted. The Authority also notes that the DGCIS data does not have a dedicated Head as has also been indicated by the petitioner and the other interested parties. The Authority, therefore, does not consider it appropriate to reference the DGCIS data. The weighted average CIF price of subject goods is evaluated at POI Rs. xxx Rs/kg. In order to arrive at the ex-factory export price, the Authority has considered adjustments on account of ocean freight, ocean insurance, commission, inland freight and port expenses to an extent xxx, xxx, xxx, xxx Rs./kg respectively on the basis of the data provided by the petitioners and also the data provided by the importers. The weighted average ex-factory export price of all grades of subject goods in POI comes to xxx Rs./kg.

DUMPING MARGIN

The rules relating to comparison provides as follows:

"While arriving at margin of dumping, the Designated Authority shall make a fair comparison between the export price and the normal value. The comparison shall be made at the same level of trade, normally at ex-works level, and in respect of sales made at as nearly possible the same time. Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are demonstrated to affect price comparability."

The Authority has carried out comparison of weighted average normal value with the weighted average ex-factory export price for evaluation of dumping margin.

The Authority notes that M/s SLG has requested for a grade to grade comparison for evaluating dumping margin. The Authority notes that in the earlier investigation, weighted average approach for evaluating dumping margin was adopted. In the present review, the Authority notes that the Product Under Consideration remains the same and that none of the exporters have cooperated by providing grade wise information in the structured questionnaire sent to the exporters. The Authority, therefore, on the basis of the best available information and also keeping in view the methodology as adopted in the earlier initial investigation has in the present review evaluated the dumping margin by comparing the weighted average normal value of all grades of HFRM with the weighted average ex-factory export

price of all grades of HFRM in the POI. The dumping margin comes as under.

Exporters/Producers	Normal Value	Export Price	Dumping Margin (%)
All Producers/exporters of China PR	***	***	47.44

D. INJURY, CAUSAL LINK AND DETERMINATION OF INJURY

Under Rule 11 supra, Annexure-II, when a finding of injury is arrived at, such finding shall involve determination of the injury to the domestic industry, ".....taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

For the examination of the impact of the imports on the domestic industry in India, we may consider such indices having a bearing on the state of the industry as production, capacity utilisation, sales quantum, stock, profitability, net sales realisation, the magnitude and margin of dumping, etc. in accordance with Annexure II(iv) of the Rules supra.

The following submissions have been made by various interested parties:

1. M/s DGP Hinoday Industries Ltd. Pune and M/s G.P. Electronics Limited, Nasik.
 - (i) The review should be carried out as per Rule 23 of the Anti-Dumping Rules. All critical parameters in the review investigation need to be established as per the period of investigation. Domestic industry has not been able to realize its fair selling price and that it may close for timely action not being taken.
 - (ii) Out of the five major producers who were a party to the petition filed by the domestic industry on 17.2.1998, three producers namely M/s Ferro Magnets & Allied Products Ltd., M/s Magnetix India Ltd and M/s Permanent Magnets Ltd have closed down their operations as they could not withstand the pressure of the declining selling prices on account of unfair dumping of subject goods from China.
 - (iii) The petitioners have been informed that employment potential is one of the reasons why the Chinese Government is subsidizing this industry there. If the decline of selling prices from China is not reversed by levying anti dumping duty, the entire HFRM industry will be closed.
 - (iv) The cost of Barium carbonate has increased due to imposition of anti-dumping duty on it in November 1999, which has resulted in along with other factors increase in the cost of production of

HFRM. M/s DGP Hinoday Industries Ltd has retrenched 100 workers and the incentive of the remaining workers has gone down. The industry employment to HFRM industry which was 2500 in 1998 has come down to 700 now.

- (v) The share of imports in the total market has grown from 1462 Mts in 1998-99 to 1767 in 1999-2000. On the other hand, the share of domestic industry has declined from 5342 Mts in 1998-99 to 5242 Mts in 1998-99 to 5205 Mt in 1999-2000. The domestic selling prices have not increased though they were meant to increase after imposition of anti-dumping duty. As against the selling price of Rs.50 per kg at the time of filing the first petition in 1998, the current selling price has decreased to Rs.34 per kg this year on account of the following reasons:-
 - (a) Importers have indicated ring magnets are magnets only if a speaker or any other product is made and that anti dumping duty cannot be levied on HFRM as they were not magnets at all.
 - (b) The Hard Ferrite Ring Magnets are imported in bunch with the other components being under invoiced so as to avoid anti dumping duty on the subject goods.
 - (c) Magnets made in China are routed through other countries
- (vi) The domestic plants which have been closed were making operating profits and it was only on account of dumping that they suffered and started making losses.

The domestic petitioners are suffering from price erosion while they can bear the cost of over capacity, they need protection from dumping. The point of over capacity and internal competition as raised by the users is irrelevant and that the domestic industry has suffered substantial losses on production.

In response to the disclosure, the following submissions have been made

The Authority has though on the one hand proposed to adopt for this review investigation the weighted average approach for determination of normal value, export price and dumping margin irrespective of the different sizes and grades of HFRM being produced and imported in view of the insufficient information with no cooperation from the exporter, but on the other hand has proposed to consider the issue of different grades while recommending the type of duty. It is not mentioned as to on what basis the same has been considered. We request the Authority to please clarify the same.

The determination of NIP at Rs. xxx per kg is much lesser than Rs. xxx as has been asked by us in our petition. We request the Authority to allow us to see further details on the basis adopted for arriving at the NIP of Rs. xxx. We reserve our right to comment on the same.

2. M/s Strategic Law Group (representing M/s Salora International, M/s Ahuja Radio, M/s Karismatic Sounds) and M/s Magnet User's Association have made the following submissions:

I

- (i) Several domestic plants were based on the export projections. In fact even today with only two manufacturers of HFRM in India, there is gross over capacity in the Indian context.
- (ii) The closure of the three petitioners has not been on account of any alleged dumping but rather on account of severe internal competition within the industry in India. M/s Magnetics India Ltd. have accumulated loss of Rs.16 crores prior to the commencement of imports of HFRM. The unit was a "sick" unit as defined under the SICA way back in 1996. At the time of HFRM-1, M/s Ferro-Magnets was already making losses. This was primarily on account of the unviable size of the plant. M/s Permanent Magnets had unreasonably high overheads and had also other ventures such as real estate projects and partnership firms unrelated to the manufacture of HFRM. The company had taken loans against non-existent stocks and the lenders forced its closure. Thus, it is clear that the three other producers of HFRM closed for various reasons unrelated to any alleged dumping.
- (iii) There has been no declining trend on imports of HFRM and there is sufficient evidence to show this. The global HFRM industries has several players including a number of private enterprises

in China and other countries such as Taiwan, Korea, Malaysia and Indonesia all of whom sell at similar prices globally.

- (iv) The prices of Barium Carbonate as the main raw material for HFRM in case of M/s G.P. Electronics has decreased.
- (v) The claim of petitioners that they are compelled to reduce employment in the industry should be looked into in view of the increased automation. In the petition itself, the petitioners have stated that the employment has gone up from 420 in 1998-99 to 426 in 1999-2000.
- (vi) If the petitioners were selling good quality magnets at Rs.34/- per kg., then why would the importers import magnets at the landed cost of which is between Rs.40/- to Rs.45/- per kg. It is imperative that the D.A. examines the issue fully and conclusively.

In response to the disclosure, the following submissions have been made

- (a) It may be mentioned that the domestic industry has itself highlighted the fact that they are suffering injury on account of imports from various countries / sources including China. This amply proves that the domestic industry is also of the clear view that the injury, if any, is caused to them due to imports from other countries. The role of china is non-existent as anti-dumping duties are already in place. Thus, there is an absence of causal link even as per the

admission of the domestic industry itself. Since the essential ingredients for imposition of anti-dumping duties are not satisfied, the Hon'ble Designated Authority should drop the review proceedings on this ground alone.

The Authority after noting the above submissions observes the following:

- (i) Production of subject goods by domestic industry has decreased from 5843.20 MT in 1998-99 to 5108.8 in POI (annualised)
- (ii) Sales of subject goods by domestic industry has decreased from 5843.20 MT in 1998-99 to 5363.28 MT in POI (annualised)
- (iii) Capacity utilisation of domestic industry has decreased from 50.85% in 1998-99 to 41.55% in POI
- (iv) The Net Sales Realisation (NSR) has decreased from Rs.41.42/kg to Rs.39.13/kg..
- (v) The NSR in POI is below the Non Injurious Price (NIP) as evaluated in the review period of investigation thereby leading to financial losses to the domestic industry.
- (vi) The Authority notes that demand has not been a contributing factor to the injury caused to the domestic industry and that in order to remove effect of any inefficiencies on the evaluation of price undercutting caused by dumped imports on the selling price of the

domestic industry, the Authority has appropriately normated the cost of production of the subject goods by benchmarking best utilisation norms on raw materials, utilities etc.

The above factors collectively and cumulatively indicate that the dumped imports have continued to keep the prices depressed in the Indian market causing injury by way of depressed net sales realisation leading to financial losses to the domestic industry and that continuance of anti dumping duties is warranted to protect domestic industry from the injury caused by price depression due to dumped imports.

Other issues

The following submissions have been made:

1. M/s DGP Hinoday Industries Ltd and M/s GP Electronics Limited
 - (i) The DA should increase the non-injurious price, fix anti dumping duty on fixed basis, and in dollar terms.
 - (ii) The total cost of HFRM in the PA System is less than 2% and cannot be waived as reason for destruction of PA industry.

In response to the disclosure, the following submissions have been made

- (i) The purpose of levying anti dumping duty is to provide protection to the domestic industry against

the dumping by exporters. In this case the domestic industry had the experience of the effects of levying anti dumping duties in different manner i.e. both on the fixed and variable basis. Based on the experience of the domestic industry when originally the anti dumping duty had been levied on fixed basis, the imports were restricted and the sales of the domestic industry increased. However when at the time of final findings the duty was changed to variable basis, the imports again increased and the effect of duty was neutralized and three out of the five companies in the domestic industry had to close down their operations. The Domestic Industry understands that the importers/traders are manipulating the import prices because of their strong nexus with the exporters. This is clear from the various transactions during the period of investigation as mentioned above. The contention of the petitioner that there has been no effect of anti dumping duty levied on variable basis can be substantiated from the fact that the present market price of HFRM is Rs.34 per kg as against the landed cost ceiling fixed at Rs.36 per kg as determined in the earlier final findings.

(ii) The levying of the anti dumping duty on fixed basis shall leave no scope for the importers to benefit from over invoicing and or under invoicing and shall serve the real purpose of levying anti dumping duty. To substantiate our claim we are enclosing herewith a press release published in Financial Express dated 20th September,2001 wherein DRI has expressed concerns over the commercial frauds in international trade.

(iii) We have already in our several communications to the Authority strongly urged to fix the Anti Dumping Duty on fixed basis rather than Variable Basis as this can only save the industry from further injury as the imposition of Anti Dumping Duty on variable basis have failed to give due protection to the Domestic industry against the unfair dumping of imported subject goods.

2. M/s Strategic Law Group representing Salora International, M/s Ahuja Radio and M/s Karismatic Sounds and Magnet Users Association have made the following submissions:

(i) It is conceded that the data as compiled by DGCIS is not suitable for HFRM importers. The private source from which petitioners have compiled data has been kept confidential. As per consistent practice of the DA and for the sake of equity proceedings between the interested parties are always held in an adversial manner with each party having the opportunity to examine and comment upon the information provided by the opposing party. By with holding the source of information, the fundamental tenet is being denied to the consumer industry.

(ii) The product is not conducive for the imposition of fixed duties, given the several varieties of HFRM and that it is a settled principle that reference value is a better method when imports might be under valued or the real threat is from cheap imports.

(iii) The standard input output norms are not available for most of the electronic products and the consuming

industry depends on DEPB for which there is no waiver of anti dumping duties for exports.

- (iv) The same petitioners prior to the availability of imports resorted to cartel pricing as was so elaborately stated in HFRM-1.
- (v) The Indian domestic producers sell HFRM globally at the same price, which was admitted at the time of public hearing. Therefore, the Indian domestic consumers should not be compelled to pay higher prices to subsidize HFRM exports by the petitioners. The high HFRM prices will jeopardize the Indian exports for PA systems and amplifiers system that need competitive priced HFRM in the absence of advance license benefit.

In response to disclosure, the following submissions have been made

- (a) The Importers must stress that the Hon'ble Designated Authority cannot look at dumping duties in isolation without the impact on exports. The Hon'ble Designated Authority is an arm of the same Ministry and having one action deter exports, in an otherwise export promotion environment of the Ministry and the Government of India is devastating. It may be noted that cost of HFRM as pointed by the petitioners at 2% in PA systems is totally misconceived and incorrect and it could be as high as 15% to 20%.
- (b) It is urgently and sincerely requested that the Hon'ble Designated Authority take in to account the impact of enhanced duties on a stable export industry.

(c) The disclosure statement indicates that the Honourable Designated Authority "proposes to look at the issue of different grades, efficacy of the reference value and as to whether the domestic industry has got the desired protection, consistent practice of such cases for recommending the type of duty".

In this connection, we would respectfully submit that since this is only a review petition, it would not be appropriate to change the mode or type of duty. This would also be consistent with the approach adopted by the Designated Authority in this very case with regard to the dumping margins. We, therefore, urge that the reference value in rupee terms must continue in view of the above submission alone. Further, the reference value is perfectly justified in this case where the Designated Authority proposes to reduce the various sizes as well as grades to a common denominator on weight basis. Obviously, it cannot be the objective of the Designated Authority to charge the same amount of anti-dumping duty on goods which are coming at vastly different prices. By changing the mode to a fixed duty would only mean that the low priced as well as the high priced magnets will bear the same amount of duty, which would go against the principle of natural justice.

(d) With reference to the imposition of duties on the prevailing \$ rate of exchange, it is submitted that the Hon'ble Designated Authority refrain from this action in this review petition, especially in light of the fact that import costs have already spiralled given the recent slide of the rupee and the fact that the DEPB scheme does not re-imburse anti-dumping duties.

E. Landed value

The landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the customs under Customs Tariff Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

F. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES

The Authority notes that the review has been initiated on the representation of the domestic industry regarding increased dumping and thereby consequential injury to the domestic industry. The user industry has indicated the effect of anti dumping duties on the export competitiveness of the PA Systems which use the subject goods. The Authority notes that the user industry has indicated non-refund of anti dumping duties under the DEPB route of the EXIM Policy. The Authority notes that the submissions on DEPB incentive of the user industry need to be considered under the ambit of EXIM Policy appropriately by the concerned authority. The Authority recognises that the continuance of anti dumping duties might affect the price levels of the subject goods and would therefore also have an effect on the products manufactured using these subject goods, however, the continuance of levy of anti dumping duties would lead to fair competition in the Indian market as the purpose of levy of anti dumping duties is to redress the injury caused to the domestic industry on account of advantage gained by the exporters through unfair trade practices of dumping. The restoration of fair play in Indian market would also prevent decline of domestic industry and help to maintain availability of wider choice of subject goods to users and consumers. The continuance of levy of anti dumping duties would in not restrict imports of subject goods from the subject country in any way. The Authority notes

the submissions on circumvention of anti dumping duties by way of misdeclaring country of origin, clearing subject goods by calling unmagnetised HFRM as not magnets and phenomena of bunching being resorted to thereby overinvoicing. The Authority notes that in view of these, the domestic industry has requested for levy of fixed duty rather than the variable duty. The Authority notes that the HFRM even in unmagnetised form would fall under the subject goods category since it is a technical requirement to supply subject goods in unmagnetised form and therefore even the unmagnetised HFRM are the subject goods under consideration as also clarified in the para B(A)(3). As regards misdeclaration on country of origin is concerned, this phenomena needs to be checked carefully at the time of import by the Customs Authority and changing type of duty cannot arrest the two types of circumvention phenomena as indicated above. As regards bunching of subject goods and consequential over invoicing of subject goods to escape anti dumping duties is concerned, the Authority has in the foregoing para C, indicated that the contention of the petitioner on certain consignments of subject goods being imported prices supposedly exorbitant price was not found to be tenable after verification. The Authority also notes that the petitioner's net sales realisation (both domestic producers) in the POI is above the reference level price, which indicates that the reference level as fixed by the Authority has been effectively able to keep net sales realisation above the level fixed earlier. Also in view of the fact that these are variety of grades with different prices and that weighted average approach on dumping margin has been adopted, it would be appropriate to levy the anti dumping duties by a variable form of duty as done in the earlier investigations.

G. CONCLUSIONS:

It is seen, after considering the foregoing that:

- a. The subject goods exported from the subject country have been exported to India below its normal value.
- b. The domestic industry has suffered material injury by way of depressed Net Sales Realization (NSR) on account of price suppression caused by low landed prices of the dumped subject goods from the subject country leading to financial losses.
- c. The injury has been caused to the domestic industry by dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country. The authority recommends anti-dumping duty on imports of all forms/grades of subject goods falling under Chapter 85 originating in or exported from the subject country. HFRM of any grade with sizes as indicated in para B(A)(3) would also attract the anti-dumping duties.
- d. It is also felt that withdrawal/discontinuance of anti dumping duty will further accentuate dumping and consequential injury to the domestic industry.
- e. It was considered to recommend the amount of anti-dumping duty equal to the margin of dumping or less so as to remove the injury caused to the domestic industry. Accordingly, it is proposed that definitive anti dumping duties equal to the difference between the landed value and amount as indicated in column 3 below be imposed, by the Central Government on all grades of subject goods originating in or exported from PR China falling under

Chapter 85 of the Customs sub-heading 8505.19 of the Customs Tariff.

1	2	3	
Sl. No.	Name of the exporter/ producer	Product	Amount (US\$/MT)
1.	<u>PR China</u> All exporters/producers	HFRM of all grades and sizes as indicated in Para B(A)(3)	1123.8

An Appeal against this order shall lie to the Customs, Excise, Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act supra.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority